15.24½ hrs.

[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*].

DR RAM SUBHAG SINGH (Buxar): What about Midnapore firing ? When will they give a reply ? So many murders took place in Midnapore jail.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K. C. PANT) : Regarding this question, I have made enquiries and we have got some information. We are getting some more information on the subject.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Can you tell us how many persons have been murdered ? Can you tell us how many prisoners have been murdered ? Can you tell us how many persons have been injured ? Will you institute an enquiry into the matter ?

SHRI K. C. PANT : An enquiry will be instituted. We are in communication with the West Bengal Government in this matter. I don't have the figures at present here.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : मरने वालों का नम्बर कितना है और जख्मियों का कितना ?

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگانوں) :- مرنے والوں کا نمبر کتنا ہے اور زخمیوں کا کتنا -]

सभापति महोदय : अगर फिगर्स अभी आप के पास नहीं हैं तो बाद में दे दीजियेगा ।

DR. RAM SUBHAG SINGH : This firing was resorted to on Tuesday and so many persons have died ; dead bodies ought to have been burnt, by now. The superintendent of police was there ; the jailors were there. Why should there be so much of delay ? Is this the way Government functions there ? This happened on Tuesday and today is Friday.

SHRI K. C. PANT : I have already given whatever information I have.

DR. RAM SUBHAG SINGH : It is a great dereliction of duty ; it shows the bankruptsy of the Government.

He can take the figure from me. Over a dozen persons have been murdered.

15.26 hrs.

RESOLUTION RE: PRICES OF ESSENTIAL ARTICLES—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further discussion of the following resolution moved by Shri Indrajit Gupta on the 20th November, 1970 :—

> "This House views with grave concern the galloping prices of all essential articles of popular consumption, and demands that effective measures be taken to hold the price-line."

Now, Shri Ram Sewak Yadav.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : In the morning, a reference was made to the strike in the IAC...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, आई० ए० सी० के बारे में...

MR. CHAIRMAN : Only Shri Ram Sewak Yadav's speech will go on record. The observations made by others will not go on record.

SHRI DHIRESWAR KALITA :**

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि आज का राक्षस अगर कोई हो सकता है तो वह बढ़ती हुई मंहगाई है। आज सारे देश के छोटी आमदनी वाले लोगों को और मध्यम आमदनी वाले लोगों को यह राक्षस आये दिन हड़पता रहता है। जब इस विधेयक

**Not recorded.

पर बहस चल रही है तब मैं जल्दी जल्दी में बढ़ती हुई मंहगाई को ले कर एक दृष्टिकोण आप के सामने रखना चाहता हूं।

अगर हम बढ़ती हुई मंहगाई को देखें तो उस के दो अंग हैं। एक तो वह चीजे हैं जो जिन्दगी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और दूसरी वह चीजें हैं जो शौक की चीजें हैं। आज हिन्दुस्तान में जो सब से बड़ी चिन्ता है वह जिन्दगी की जरूरी चीजों के बारे में है। शौक की चीजों के दाम बढ़ें तो उस की चिन्ता मुझे नहीं है। इसके साथ ही जहां तक मंहगाई का सम्बन्ध है, कारखाने की चीजों के दामों और खेतों में जो चीजें पैदा होती हैं उनके दामों में जो बड़ा भारी असन्तुलन है उसका मतलब है। इस लिए अगर हम सचमुच चाहते हैं कि मंहगाई रुके तो हम को दो मुख्य मुद्दों में जाना और देखना पड़ेगा। पहली चीज तो यह कि जिन्दगी की जरूरी चीजें जितनी हैं उनके भाव न बढ़ें। आप देख रहे हैं कि जिन्दगी की जरूरी चीजें जितनी हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, सीमेंट हो, लोहा हो, अन्न हो या दवा हो, जब उनके दाम बढ़ते हैं तब छोटी आमदनी वाले लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है, और यह दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बढ़ते हुए मूल्यों को रुपये की दृष्टि से देखें तो रुपये की कीमत घट कर दो या ढाई आने के बराबर रह गई है। इससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं रह गई है।

जो शौकीनी की चीजें हैं उनके दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं। जरूरी जो जिन्दगी के लिए चीजें हैं उनके दाम इस तरह से न बढ़ सकें, इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन पर अमल करे ताकि दाम घटे और छोटी आमदनी वाले जो लोग हैं उनकी जिन्दगी आसानी से चल सके। चीजों के बढ़ते हुए दाम और लोगों की आमदनी, से जीवन की बैल गाड़ी के दो बैल हैं। जब आमदनी का बैल धीरे चले और मंहगाई का बैल सरपट भागे तो जीवन की गाड़ी टूट जाती है और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के दोनों बैल आपस में टकरा गए हैं और एक तो सरपट भाग रहा है और दूसरा पीछे चल रहा है। मंहगाई की वजह से जीवन की गाड़ी आज बिल्कुल टूट गई है। यह सरकार चाहे समाजवाद की बात करे, चाहे छोटे आदमी की बात करे, लेकिन यह तथ्य है कि आज यह सरकार मंहगाई को रोकने में असफल साबित हुई है। इस वास्ते छोटे आदमी को राहत देने वाली यह सरकार नहीं है। यह सरकार करोड़पंथी सरकार है। बड़े लोगों को राहत देने वाली यह सरकार है। कारण यह है कि बढ़ती हुई मंहगाई से अगर किसी को तकलीफ होती है तो छोटे आदमी को होती है। बढ़ती हुई मंहगाई से सरमायेदार को कष्ट नहीं होता है, बड़े अफसर को नहीं होता है सत्ता की राजनीति में जो नेता लोग हैं, उनको नही होता है। बाकी इस देश के सभी लोग इस मंहगाई से दुखी हैं। सरमायेदार, सत्ता में आज जो नेता लोग हैं तथा जो अफसर हैं इन का त्रिकोण बना हुआ है और यही सारी सत्ता का संचालन कर रहे हैं। चूंकि इनको मंहगाई अखरती नहीं है, इसलिए उस पर आज काबू पाने का कोई प्रयास नहीं होता है। अगर आप सच्चे दिल से मंहगाई रोकना चाहते हैं तो मैं कुछ सुझाव आप को देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप उन पर अमल करेंगे।

इस सरकार के पास आज कोई निश्चित और ठोस दाम नीति नहीं है जोकि होनी चाहिये। जब तक निश्चित ठोस दाम नीति नही होगी यह मंहगाई रुकने वाली नहीं है। फिर चाहे इसको रोकने से बारे में कितनी ही बातें आप करते रहें। तब ये सारी बातें निरर्थक होंगी। मेरा पहला सुझाव यह है कि खाद्यान्नों के बारे में पहले आप एक नीति बनायें और नीति यह बनाएं कि दो फसलों के

[श्री राम सेवक यादव]

बीच में सेर पीछे इनके दामों में आना से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा । अगर आपने ऐसा किया तो छोटी आमदनी के जो लोग हैं कम से कम उनको खाने का कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा और उनका पेट भर सकेगा ।

इसी तरह से कारखानों में बनी जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं, जैसे कपड़ा है, मिट्टी का तेल है, सिमेंट है, लोहा है, दियासलाई आदि हैं, इनके बारे में मेरा सुझाव है कि इस तरह की जिन्दगी की जो जरूरी चीजें हैं उनके दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से आगे न जाएं । उसी के बीच में मुनाफा है, उसी के बीच में सरकारी कर है । जो कुछ भी कीमत हो वह लागत खर्च से ड्योढ़े से ज्यादा न हो । आज क्या होता है ? आज मिट्टी का तेल 6 या 7 या 8 पैसे बोतल में उनको पड़ता है । लेकिन जब वह बाजार में बिकने के लिये आता है तो बारह आने बोतल और कहीं कहीं एक रुपया बोतल बिकता है । इस तरह से जो बढ़े हुए दाम हैं उनमें छोटी जो जनता हैं वह बराबर पिसती जा रही है । इसी तरह से साबुन, कपड़ा लागत खर्च से तीन चार, पांच या छः गुणा ज्यादा कीमत पर बिकता है । इस वास्ते कारखानों में बनी जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम किसी भी हालत में लागत खर्च के ड्योढ़े के आगे न जाएं, इसकी व्यवस्था आप करें । जब तक इस तरह की दाम नीति नहीं बनाई जाती है, कंट्रोल की बात करना, कानून बनाना, यातायात पर प्रतिबन्ध लगाना उससे कुछ नहीं होगा और मंगाई नहीं रुकेगी ।

तीसरा सुझाव मेरा खेती में पैदा होने वाले कच्चे माल और कारखानों में तैयार होने वाले पक्के माल के बारे में है । खेती में पैदा होने वाले कच्चे माल जैसे, गन्ना, तिलहन, रुई, पटसन आदि इनके दाम और कारखानों में जो पैदा होता है जैसे चीनी, कपड़ा, लोहा आदि इनके दाम, इन दोनों दामों में कोई सन्तुलन आज नहीं है । आप पिछले दस पंद्रह साल के आंकड़े उठा कर देखें । आपको पता चलेगा कि जिस तरह से कच्चे माल और खाद्यान्नों के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा कारखानों में बनी चीजो के दाम बढ़े हैं और वे बराबर चढ़ते जा रहे हैं । जब तक कारखानों में तैयार होने वाले माल के दामों और खेती की उपज के दामों में कोई संतुलन कायम नहीं होगा तब तक कोई भी दाम नीति आप ठोस आधार पर नहीं चला सकते हैं ।

मैं एक मिसाल देता हूं । आप गन्ने के दामों को लें । कच्चा माल है गन्ना । मैं पूछना चाहता हूँ कि किसान को गन्ना पैदा करने में कितनी सहूलियत मिली है ? क्या गन्ने का बीज उसको सस्ता मिलता है, क्या आज उसको पानी सस्ता मिलता है, क्या खाद सस्ती दी जाती है ? सभी चीजें उसको मंहगे दामों पर मिलती हैं । लेकिन आप देखेंगे कि 1967-68 में गन्ने का भाव क्या था । तब वह भाव पंद्रह रुपये और सोलह रुपये क्विंटल था उत्तर प्रदेश में । 1968-69 में वह दस रुपये हो गया । अब गन्ने का भाव 7 रुपये 35 पैसे क्विंटल है । हरी क्रान्ति का नारा तो आप देते हैं लेकिन गन्ने का दाम जहां पंद्रह सोलह रुपये होता था वह आधा रह गया है और दो क्विंटल गन्ना किसान को उतना ही पैसा प्राप्त करने के लिए देना पड़ता है । ऐसी हालत में हरी क्रान्ति में क्या उसका मन लगेगा ? फिर नोट की जो कीमत है वह भी छिजती जा रही है । इस तरह से उसकी कीमत और घट जाती है । ऐसा आपने किया तो हरी क्रान्ति को भी आप मारेंगे । जब तक हरी-क्रान्ति और किसान की चीज के दामों में कोई रिश्ता आप स्थापित नहीं करेंगे तब तक यह नीति चलने वाली नहीं है ।

जब मंहगाई बढ़ती है तो सरकार अपने

कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को बढ़ा देती है। सोधी साहब जी उनके लिए मंहगाई भत्ता बढ़ाने की लड़ाई में लग जाते हैं। मैं कहूँगा कि भत्ता मत लो, लो निश्चित दामों पर चीजें। जब तक चीजों के दाम निश्चित नहीं होंगे मंहगाई भत्ता बढ़ने से भी आप चीजों की कीमतें अपनी जेब से अदा कर नहीं पायेंगे, उन को प्राप्त करने के लिए आप को अपनी जेब से और ज्यादा देना पड़ेगा। आप मृग मरीचिका के बीच दौड़ते रहेंगे और कभी . कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। यहां कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ गया, सरकारी नौकरों का और अफसरों का भत्ता बढ़ गया। लेकिन जो मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो किसान हैं, उनको कहां से मिलेगा? अगर हम अनाज की बात करें, मक्के की बात करें, चावल की बात करें तो पता लगेगा कि चार छः साल में कहीं पाव आधा सेर का दामों में फर्क पड़ा होगा, इससे ज्यादा उनके दामों में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कारखानों की चीजों के दाम एक दम आसमान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उस चीज को ध्यान में रख कर आपको नीति बनानी चाहिए।

मैं यह भी समझता हूं कि मंहगाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक बड़ी आमदनी वालों के खर्च पर रोक नहीं लगेगी। भारत सरकार के जो सचिव लोग हैं, मंत्री हैं, गवर्नर हैं, राष्ट्रपति हैं, अगर इनकी आमदनी और इनका खर्च डेढ़ दो हजार के अन्दर सीमित कर दिया जाए तो इनको भी मंहगाई का कुछ पता लगेगा और तब उस राक्षस को मारने के लिए कोई कारगर रास्ता ये ढूंढेंगे। इनको तो मंहगाई खलती नहीं है। फिर सूबों के लोग भी मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात करते हैं। आपके पास कारखाना है नोट छापने वाला नासिक में। लेकिन जब सूबों में मांग चलती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है और फिर भी जब वे मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना में हम सहायता आप की नहीं करेंगे। यह भी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। मैं कहूंगा कि नोट छापने आप बन्द करें। पैसे की जो कमी है उसको आप बिल्कुल खर्च बन्द करके और खास तौर से प्रशासन पर खर्च कम करके पूरा करें। सरकार को शौकीन और ठाट वाट के कामों पर अपने खर्च को घटाना चाहिए। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 27 लाख रुपये खर्च करके एक फव्वारा बनाया गया है। उस रुपये में कितने नलकूप लगते? अभी परसों एक मीटिंग में हमको बताया गया कि यह फव्वारा बन्द कर दिया गया है, क्योंकि बिजली का अभाव है। एक फव्वारे पर 27 लाख रुपया खर्च किया गया, जबकि पूरी दिल्ली में गरीब लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आज ऐसा लगता है कि नई दिल्ली में चारों तरफ फव्वारों की नुमायश लगी हुई है। इस फिजूल खर्ची को बन्द किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी की एक दो मंजिला इमारत है, जो बड़ी मजबूत है। लेकिन उसका दोष यह है कि उस के पड़ौस में कई कई मंजिलों की इमारतों के सामने उसका सिर झुकता है। यह बात इस सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए छैनी-हथौड़े से उसको तोड़ा जा रहा है और उसकी जगह पर चार करोड़ रुपये की एक गगनचुम्बी अट्टालिका बनाने की योजना है। इस सरकार को यह तमीज नहीं है कि पहले कौन सा काम करना है—पहले जिन्दगी की जरूरत को पूरा करें, बुनियादी कामों पर रुपया खर्च करें या शौकीनी ठाट-वाट और मौज-मस्ती के कामों पर खर्च करें।

अगर सरकार सचमुच मंहगाई को रोकना चाहती है, तो वह एक दाम नीति तय करे, अपने फिजूल खर्च पर और नोट छापने पर रोक लगाये। जो नोट लोगों के पास पहुंच गए हैं, अगर किसी तरह से, उन को जब्त करके या डीवैल्यूएशन कर के उनको खत्म किया

[श्री राम सेवक यादव]

जा सके, तो मंहगाई के राक्षस का मुकाबला हो सकेगा, वर्ना इस समय तो सरकार ने देश में ऐसी भयंकर स्थिति पैदा कर दी है कि गांवों और शहरों में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में चीन जैसी हालत आने वाली है जेब में सौ रुपये का नोट ले कर बाजार में जायेंगे और शाम को एक किलों आलू और दो गोभी के फूल ले कर चले आयेंगे और वह नोट खत्म हो जायेगा। यह मामला बहुत बिगड़ गया है।

इतनी महत्व पूर्ण बहस के लिए एक दो घंटे रखे गए हैं। वास्तव में सरकार की तरफ से यह बहस आनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पूरी आर्थिक स्थिति, आर्थिक ढांचे, व्यापक नीतियों और समाजवाद के रास्ते का सवाल निहित है। आखिर समाजवाद किस लिए? क्या इस लिए कि गरीब आदमियों का पेट न भरे, उनका तन न ढ़के, उनके रहने के लिए मकान न बनें और दूसरी तरफ गगनचुम्बी अट्टालिकायें बने, फव्वारों का निर्माण हो, दिल्ली की शानो-शौकत पर पैसा खर्च किया जाये, जबकि गांवों और शहरों में झुग्गी-झौंपड़ियां वैसे ही खड़ी रहें? अगर हमारे देश में उस तरह का निर्माण होने वाला है, तो फिर समाजवाद की तस्वीर बड़ी गन्दी होगी देश क्रान्ति के कगार पर पहुंच जायेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, और जो कुछ बंगाल में हो रहा है, वह सारे देश में हो सकता है।

इस लिए सरकार समय रहते चेते। इस पूरे मुद्दे पर, योजना पर, व्यापक रूप से बहस कराई जानी चाहिए। आखिर यह योजना किस लिए है? मंहगाई को रोकने के लिये, बेकारी को खत्म करने के लिये, वही इस समय के मुख्य मुद्दे हैं। सरकार को खुद दस पंद्रह घंटे की बहस करा के कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस तरह के घंटे की बहस से सरकार मंहगाई को नहीं रोक सकती है, यह एक रिचुअल हो गया है। सरकार इस तरह खाना पूरी कर सकती है, लेकिन वह समस्या को हल नहीं कर सकती है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अगर वे बोलना चाहते हैं, तो चेयर के पास आने के बजाये वे चिट लिख कर भेज दें। चेयर के पास आने पर माननीय सदस्यों को आवजेक्शन होता है। अगर कोई सदस्य बोल रहे हैं तो माननीय सदस्य उन के सामने से नीचे हो कर क्रास करें।—श्री रणधीर सिंह।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Is Mr Randhir Singh satisfied that there are plenty of people in the press?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, मुझे एक वह बात का बहुत दुःख है, जिस का मैं इजहार करना चाहता हूँ। मुझे उस का बड़ा अफसोस है और उस के लिए मैं हाउस से और प्रेस से माफी चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप को हाउस के आनरेबल मेम्बर्ज के बारे में जो कुछ कहना है वह कहिये, लेकिन गैलरीज या प्रैस के बारे में कोई सदस्य कुछ न कहे।

श्री रणधीर सिंह : दो दिन रोज पहले यहां पर डीबेट हुई थी और मैं ने उस वक्त कुछ बात कही थी। उस से कुछ गलतफहमी हुई है। इस लिए मैं उस को साफ करना चाहता हूं। आप ने कह दिया है कि गैलरी का जिक्र न किया जाये। लेकिन आल इण्डिया रेडियो के नुमायंदे उस दिन एक ऐसी जगह बैठे हुये थे, जहां से वह मुझे दिखाई नहीं देते थे। इस लिए मैं गलत तौर पर कुछ कह गया था। मेरी जमीर नहीं मानती कि मेरी वजह से किसी भाई को तकलीफ हो। मैं उस के लिए यहां रिग्रेट शो करना चाहता हूं मेरा ख्याल है कि आप मुझे उस के लिए माफ फरमायेंगे।

अब मैं इस रेजोल्यूशन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जिन अलफाज में यह रेजोल्यूशन है, मैं उन के खिलाफ हूं।

सभापति महोदय : आप ने अपना नाम गलत तौर पर भेजा है। आप इस रेजोल्यूशन पर बोल चुके है।

श्री रणधीर सिंह : मेरी एक एमेंडमेंट है, जिस पर मैं नहीं बोला हूं। मैं अपनी एमेंडमेंट पर बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : उस के लिए आप को बाद में बुलाया जायेगा।

श्री रामसेवक यादव : माननीय सदस्य ने उस दिन इस प्रस्ताव का समर्थन किया और आज वह इस की मुखालिफत कर रहे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्ता, के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कारगर उपाय किये जायें। इस प्रस्ताव पर मैंने जो संशोधन दिया है, उस के बारे में मैं बाद में कहूंगा। देश में महंगाई कितनी बढ़ी है, उस के अन्दाज के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1947 के मुकाबले में आज रुपये की कीमत केवल चौदह पैसे रह गई है, यानि आज एक रुपये में हम जितनी चीजें खरीद सकते हैं, 1947 में केवल 14 पैसे से उतनी चीजें खरीद सकते थे। 970 का रुपया आज 14 पैसे हो गया और 1960 में जो रुपया था वह 42 पैसे हो गया है। समझ जाइये इसी से कि रुपये की कीमत कितनी कम हुई है, मतलब कि महंगाई कितनी बढ़ रही है क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इस महंगाई को बढ़ाने की जिम्मेदारी किस की है? इस की जिम्मेदारी बिल्कुल वन हन्ड्रेड परसेंट इन की है सभापति महोदय, मंत्री महोदय, गपशप कर रहे हैं, आप जरा कहिये उन को, यह डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग डिसिप्लिन्ड रहेंगे, आप उन को कहिये आप की तरफ ख्याल रखें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : हम जवाब आप को देंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : जवाब तो आप देंगे नहीं। आप बोलेंगे अपनी तरफ और हम बोलेंगे अपनी तरफ।

तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, दाम का सन्तुलन देश में कायम रखने के लिए दो चीजों पर कन्ट्रोल की जरूरत है। कन्ट्रोल का मतलब एक उन का प्रोडक्शन और दूसरे क्वान्टिटी आफ मनी यह संतुलित होना चाहिए। क्वान्टिटी आफ मनी देश में कितनी है और प्रोडक्शन कितना है, इन दो बातों पर कन्ट्रोल रखना चाहिए। इस में अगर गड़बड़ी आ जाती है, यानों प्रोडक्शन जितनी है उस से ज्यादा पैसा आ जाता है बाजार के सर्कुलेशन में तो पैसे की कीमत कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमत ऊपर उठ जाती है। तो अर्थ-शास्त्र का तकाजा है कि जितना प्रोडक्शन समाज में हो चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो उसी हिसाब से जो सर्कूलेशन का माध्यम है मनी उस को छोड़ा जाय। लेकिन सरकार ने यही नीति शुरू से गलत अख्त्यार की। पहले तो आप प्रोडक्शन को ले लें। औद्योगिक उत्पादन समाज में आज कम होता जा रहा है बावजूद पब्लिक सैक्टर के बढ़ने के और बावजूद इस के कि हमारी मांग है कि पब्लिक सैक्टर बढ़े, नेशनलाइजेशन हो, लेकिन इस सरकार के प्रशासन की जो व्यवस्था है पब्लिक सैक्टर को चलाने के लिए वह ऐसी है कि जिस का नतीजा यह होता है कि मोटे तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। और कृषि के क्षेत्र में इन्हीं की ओर से बड़ा इस का शोर

[श्री शिव चन्द्र झा]

मचाया गया है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया है और अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है इस तथाकथित ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, यानी जितना अन्दाज था पहले उस से भी ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह यह होती है कि बावजूद इस सो-काल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के और फूड प्रोडक्शन के, दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो अब यह बीमारी साफ सामने आने लगती है कि प्रोडक्शन इतना है फिर सारी वस्तुओं के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस की जड़ में क्या है? इस की जड़ में यह है कि सरकार की जो मौनेटरी पालिसी है वह बुनयादी तौर पर गलत है। इसलिए गलत है कि इन के जो और मामले हैं खर्च के उस पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। नतीजा यह होता है कि जब किसी खर्चे को मीट करने की जरूरत होती है, उस को पूरा करने की जरूरत होती है तो सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाती है, दूसरे शब्दों में नोट छापने का रास्ता अख्त्यार करती है। रुपया जो है, मनी जो है वह एक करेंसी है और एक बैंक क्रेडिट है। हम उस की तफलील में यहां पर नहीं जायेंगे। मोटे तौर पर जो करेंसी है जो नासिक प्रेस में छपती है उस पर सरकार जाती है। अब आप देखिये कि कर्मचारियों की मांग है कि उन की तनख्वाह बढ़े चूंकि दाम बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं उस को बढ़ाना जरूरी है। अब कहा जाता है कि चूंकि वेजेज बढ़ रहे हैं इसलिए कास्ट बढ़ रही है। इस का असर होता है दाम पर और इस से महंगाई होती है और इन्डायरेक्टली हालांकि सरकार को मालूम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सरकार कहती है कि यदि वेजेज पर कन्ट्रोल रखें तो कास्ट पर कन्ट्रोल होगा और कास्ट पर कन्ट्रोल होगा तो महंगाई नहीं होगी और दाम संतुलित रहेंगे। यह गलत बात है। जो वेजेज हैं चाहे वह वर्कर्स के हों चाहे लेतिहर मजदूर के हों उन के बढ़ाने से आप समाज में एफेक्टिव डिमांड लाते हैं। आप को एफेक्टिव डिमांड की जरूरत है जिस से कि आप के कारखाने चलते हैं और सारी चीजें चलती हैं। एफेक्टिव् डिमांड को भ्रष्ट करने का रास्ता है इन का कांस्पीकुअस कंजम्पशन। उस पर कन्ट्रोल करते नहीं हैं। यह कन्ट्रोल करते हैं हकीकत में मजदूरों की तनख्वाह से जो एफेक्टिव डिमांड आती है उस पर। एफेक्टिव डिमांड जो है उस पर कन्ट्रोल करने की बात लाते हैं। यह गलत नीति है। प्राफिट पर भी कन्ट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन सरकार उस पर कन्ट्रोल करती नहीं है और मुद्रास्फीति करती है. नोट छाप कर बाजार में लाती है और नतीजा यह होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है और नोट की ज्यादा क्वान्टिटी बढ़ने लगती है, ज्यादा नोट बाजार में चलने लगते हैं और दाम का सन्तुलन समाज में नहीं रहता। तो दाम का सन्तुलन समाज में रखने के लिए लाजमी हो जाता है कि प्रोडक्शन और क्वान्टिटी आफ मनी में आप संतुलन रखें। लेकिन जो आज सरकार की मौनेटरी पालिसी है बुनयादी तौर पर उस की गड़बड़ी की वजह से यह होता है।

दूसरी बात—उस में जो सेकेंड्री पार्ट होता है वह होता है सप्लाई और डिमांड का। उस सप्लाई और डिमांड में यह जो आप के स्पेकुलेटर्स हैं वह बड़ी गड़बड़ी पैदा करते हैं। उनके खिलाफ इतनी आवाज यहां पर उठाई जाती है कि यह जो इंटर्नल ट्रेड है इस को आप को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज जो भी आप का प्रोडक्शन कृषि के क्षेत्र में होता है और बाजार में नहीं आता है, होर्डर्स होर्ड कर लेते हैं और वह देखते है कि किस मौके पर हम इस को बेचें। जिस भी वस्तु का उत्पादन हुआ है उस का सर्कुलेशन होने के लिए उस को बाजार में जाना चाहिए। लेकिन इन्टर्नल ट्रेड में यह प्राफिटियर्स कदम

कदम पर बैठे हुए हैं, स्पेकुलेटर्स पर बैठे हुये हैं प्राफिट के लिए। नतीजा यह होता है कि जो भी प्रोड्यूस किया हुआ सामान है, पैदा की हुई वस्तु है वह बाजार में आ नहीं पाती है। तो यह जो सप्लाई है इस को कन्ट्रोल करने के लिए आप को इंटर्नल ट्रेड को हाथ में लेना होगा। और दूसरी बात—सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन में आप को परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन के लिए मैंने शुरू में कहा कि कृषि के क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आप को बुनयादी परिवर्तन की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में बुनयादी परिवर्तन लाने के लिए जमीन की मिल्कियत की जो बात है उस में आप को परिवर्तन लाना होगा। यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के युग का जो तरीका है प्रोडक्शन का उस से काम चलने वाला नहीं है। आप को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना होगा। यह अनएकोनामिक होल्डिंग्स जो हैं दो दो ढाई ढाई की; यह जो फ्रैगमेंटेशन आफ लैंड है, इस से यह काम नहीं चलेगा। इस के लिए बड़े पैमाने पर सहकारी ढंग से आप को खेती करनी होगी दूसरे शब्दों में, हिन्दुस्तान के इतिहास के संदर्भ में विनोबा जी यह बात रख रहे हैं ग्राम दान के रूप में। लेकिन आप के हाथ में कानून है, कानून के जरिये आप यह बात कर सकते हैं कि जमीन की मिल्कियत तमाम गांव की हो। गांव का कब्जा जमीन पर होगा तो इस से क्या होगा कि लैंडलेस लोग जो हैं उन की समस्या का हल हो जायेगा और साथ साथ खेती का पैमाना भी बड़ा होगा जिस से आप वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में बुनयादी परिवर्तन की जरूरत है। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बुनयादी नीति की जरूरत है। वह क्या नीति है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप ने कर दिया। बड़ा ताल ठोकते हैं कि कमाल कर दिया, दुनियां उलट दी। ऐसा किसी ने नहीं किया था। लोग कहते हैं कि पंडित जवाहर लाल जी ने भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, अब हम लोगों ने कर दिया। जो किसी ने नहीं किया वह हमने किया। लेकिन कल बैंक पर बहस हो रही थी, मैं ने कहा कि अभी भी बैंक जो हैं वह प्राइवेट सैक्टर में हैं। विदेशी बैंक हैं उन का राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है और एक इंटीग्रेटेड पालिसी की जरूरत है। इन सब चीजों पर आप को कन्ट्रोल करना होगा।

यह मोनोपली हाउसेज जो हैं अध्यक्ष महोदय, इन मोनोपली हाउसेज पर आप को कन्ट्रोल करना है। मोनोपलिस्ट्स का खात्मा करना है। टाटा बिरला राज जो हैं उन की दुनिया जो बसाई हुई है उस को खत्म करना है। 75 मोनोपली हाउसेज हैं जो आज सब कुछ कन्ट्रोल करते हैं। इतिहास कहता है हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रान्स को कौन कन्ट्रोल करता है? फ्रांस को 200 परिवार कन्ट्रोल करते हैं और अमेरिका का भी वही हाल है। अमेरिका को भी 200 परिवार मोटे तौर पर कन्ट्रोल करते हैं। आज हिन्दुस्तान को कौन कन्ट्रोल करता है? यह 75 मोनोपली हाउसेज कन्ट्रोल करते हैं। यहां की सारी अर्थ-व्यवस्था को यह 75 मोनोपली हाउसेज कन्ट्रोल करते हैं। आजकल वह अशोक साहब उधर चले गये। उन्होंने एक पुस्तिका लिखी—हू ओन्स इण्डिया। मैंने वह किताब पढ़ी। उस में उन्होंने साबित कर दिया है कि यह जो मोनोपलिस्ट लोग हैं, उद्योगपति हैं एकाधिपत्य वाले यह हकीकत में यहां की अर्थव्यवस्था को कन्ट्रोल कर रहे हैं। तो वह सर्किल जो है वह और नैरो डाउन होता जा रहा है। इसलिए यह मोनोपली हाउसेज जो हैं उन पर कब्जा करने की जरूरत है। मतलब यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए लाजिमी हो जाता है कि आप मोनोपली हाउसेज का राष्ट्रीयकरण करें। एक बीमारी

[श्री शिव चन्द्र झा]

चल गई है— यह कहने की कि राष्ट्रीयकरण से कुछ नहीं होता है, इस से हम घाटे में जाते हैं यह रामबाण नहीं है। सभापति महोदय, आप को याद होगा ऐसा ही लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में कहा करते थे, इतने से काम नहीं चलेगा और चीजों की जरूरत है। लेकिन यह एक बड़ा कदम है, एक लाजमी कदम है, उस में हम सुधार लायेंगे, अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे मुल्कों में जहां राष्ट्रीयकरण की बात हुई है, रूस या अन्य मुल्कों में, वहां भी आज परिवर्तन आ रहे हैं, जो ओवर-सैन्ट्रलाइज्ड था, उस को डी-सैन्ट्रलाइज करने की बात चल रही है, हमें भी अपने औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन करना होगा, लेकिन इस सब के लिए एक योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था की जरूरत है, उस में सुधार की जरूरत है।

16 hrs.

आज आप के योजना-आयोग पर बहस नहीं हो सकी, आप का योजना-आयोग आज दम तोड़ रहा है। सभापति महोदय, आप को याद होगा, आजादी की लड़ाई के दिनों में देश की अर्थ व्यवस्था के लिए एक नया ढांचा बनाने के लिये पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक प्लानिंग कमेटी बनाई थी और उन की मुखालफत आप के तथाकथित खादीवादियों ने की थी। उन लोगों ने कहा था कि जवाहर लाल नेहरू शेखचिल्ली का काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग कमेटी बनी वे खुद उसके चेयरमैन बने, एच० वी० कामथ भी उस में थे। उसी दृष्टिकोण से आजादी के बाद उन्होंने योजना-आयोग बनाया, लेकिन आप का यह योजना आयोग दम तोड़ रहा है, उस में और आप के मन्त्रालयों में क्लैश चल रहा है, वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंक रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से काम नहीं चल रहा है, तुम हमारे मुताबिक योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे हो और ये कहते हैं कि तुम हम को डिक्टेट नहीं कर सकते। योजना आयोग कहता है कि हम को फाइनान्स नहीं मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि योजना आयोग में सोचने की ओरिजनल ताकत खत्म हो गई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सोचने का काम योजना आयोग ने नहीं किया, दूसरे लोगों को करना पड़ा, इसी तरह से और भी दूसरे बहुत से काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। इस लिये योजना आयोग में पूरे परिवर्तन की जरूरत है। इस समय ऐसे लोग उसमें घुस गये हैं जो पब्लिक सैक्टर को सैबोटाज करना चाहते हैं, जिन का उसमें विश्वास नहीं है, जो योजना आयोग की दीवारों के अन्दर रह कर हमारी नीतियों पर कुठाराघात कर रहे है, हमारे पब्लिक सैक्टर पर कुठाराघात कर रहे हैं और इसको देखने वाला देश में कोई नहीं है। जिस योजनाबद्ध तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, अपने एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में तरक्की लाना चाहते थे, जिसके द्वारा हमारी मानिटरी पालिसी अच्छी होती, क्वान्टिटी आफ मनी में अप लिफ्ट आती—वह सब कुछ नहीं हुआ—यही बुनयादी बात है।

इस लिए सभापति महोदय, जरूरी हो जाता है कि तमाम पालिसीज का फिर से एप्रेजल हो, फिर से उन पर पुनर्विचार किया जाय—इसी दृष्टिकोण से मैंने इसमें अपना संशोधन दिया है। इफेक्टिव मेजर्ज लेकर सरकार डेफिसिट फाइनेन्सिंग को कन्ट्रोल करे। आज डेफिसिट फाइनेन्सिंग सरकार की खुराक बन गई है, डेफिसिट फाइनेन्सिंग को नशे के रूप में ग्रहण कर के सरकार अपना काम चलाने का प्रयत्न करती है, लेकिन कटौती करने का प्रयत्न नहीं करती। आप की ऐसी बहुत सी मदें हैं जिनमें कटौती हो सकती है।

पाल बैरन ; अमरीन इकानामिस्ट ने कहा है कि आप के यहां 500 करोड़ रुपये प्रतिसाल का गलत कामों पर खर्चा होता है। डा० लोहिया ने कहा था कि प्रधान मन्त्री पर 25 हजार रुपये प्रतिदिन लगता है और आज अगर आप हिसाब लगाये तो प्रधान मन्त्री पर 50 हजार रुपये प्रतिदिन का खर्चा होता है, इसी तरह से मन्त्रियों पर खर्च होता है, इन को 35 हजार रुपया मिलता है, लेकिन यदि इन की आमदनी का हिसाब लगायें तो वह कहीं ज्यादा है। इस लिए चाहे हदबन्दी लगायें या जैसे भी करें, अगर खर्च पर सीलिंग लगायें, दो हजार रुपये से ज्यादा खर्च न हो तो आप की डेफिसिट फाइनेन्सिग रुक सकती है। डेफिसिट फाइनान्सिंग आज एक चोरी का रास्ता बन गया है, पैसे की पौकिट-मारी है, रुपये की कीमत की पौकेट-मारी का तरीका है—यह पौकेट-मारी जो सरकार कर रही है, अगर इसको बन्द कर दे, तो आप के यहां दामों का सन्तुलन हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं और अपने संशोधन पेश करता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सभापति महोदय, अभी हमने पिछले वक्ता से यह सुना कि डेफिनिट फाइनेन्सिग बहुत जोरों से हो गया है। मुझे याद आता है वह दिन जब इस देश की प्रधान मन्त्री ने हिन्दुस्तान का बजट पेश किया था और उस बजट को पेश करते हुए उन्होंने बड़े दम के साथ, घमंड के साथ यह कहा था कि हम 225 करोड़ रुपये का डेफिसिट फाइनेन्सिग कर रहे हैं, परन्तु आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है कि यह खप जायेगा। प्रधान मन्त्री जी ने, जो उस समय वित्त मन्त्री भी थीं, आश्वासन दिया था कि हम देश में कीमतों को नही बढ़ने देंगे। लेकिन जब कीमतें बढ़ने लगीं, तो अपना बोझा उठाकर चव्हाण साहब के कन्धों पर फेंक दिया और मुझे ताज्जुब लगा, उस दिन जब चव्हाण साहब ने कहा कि बढ़ते हुए आर्थिक विकास में चीजों की कीमतें बढ़ना लाजमी है। या तो चव्हाण साहब वित्त मंत्रालय में जाकर अन्धेरे में टटोल रहे हैं कि वित्त मन्त्रालय क्या है, वरना वित्त मन्त्रालय का मन्त्री यह वक्तव्य नहीं दे सकता कि बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था में चीजों की कीमतें बढ़ना लाजमी है। मैं मानती हूँ—यह तो हमने इंटर-मीडिएट और बी० ए० में पढ़ा था कि बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था में चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन यह उस वक्त होता है जब हमारे मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यदि उसी अनुपात से कीमतें बढ़ती हैं तो फिर कोई फर्क की बात नहीं है, अगर देश की प्रति व्यक्ति आय पांच रुपये बढ़े और कीमतें पौने-पांच रुपये बढ़ें तो उसमें कोई घाटा नहीं नहीं है, वहां तक हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन चव्हाण साहब भूल गये कि आज हमारी आर्थिक व्यवस्था एक तरफ इतनी नीचे चली जा रही है, उत्पादन बहुत जोरों से घट रहा है, दूसरी तरफ चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप खुद एक कृषि इलाके से आते हैं, आप को मालूम है कि चावल का दाम थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जिस तरह से चावल की पैदावार बिहार में हुई, मैं अभी वहां से लौट कर आई हूँ, मैंने सुना है कि आन्ध्र प्रदेश का चावल जो परमिट लेकर बिहार में भेजा गया था, अभी बिहार के बाजारों में बोरो में बन्द पड़ा है, एक छटांक भी नहीं बिक रहा है। गेहूं के दाम गिर रहे हैं, चीनी के दाम गिर रहे हैं और चावल के दाम भी गिरने वाले हैं। आज किसान को यह बात मालूम हो जानी चाहिए कि उसको उसकी उपज का सही पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ खाद्यान्न को छोड़कर हर चीज के दाम बढ़ गये हैं। किसान जब भी कोई चीज खरीदेगा, उसे मंहगे दामों पर खरीदनी होंगी।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

नमक, जिसके लिये गान्धी जी सत्याग्रह करते थे, हम इस पर टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उसे हर गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत 12 परसेन्ट ज्यादा बढ़ गई है। आज कोई भी चीज किसान और मजदूर खरीदने जाएगा, उसे कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलेगी। हम उत्पादन की बात करते हैं—एक तरफ उत्पादन घट रहा है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि रोजगार देंगे, कैसे देंगे? मैं पूछना चाहती हूं कि लौली-पौप की तरह से देश को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है?

यहां हम देखते हैं उत्पादन बढ़ाने की बात की जाती है, रोजगार देने की बातें कही जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं—लोहे का कंट्रोल रेट 900 रुपये टन है। बदकिस्मती इस देश की यह है कि इस देश का अन्धेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। मैं यह मानती हूँ कि हमको फारन एक्सचेन्ज कमाना जरूरी है, लेकिन अपने मुल्क की हालत भी जरा देखिये—बेरोजगारी बहुत जोरों से बढ़ रही है। यह बात मैं ही नहीं कह रही हूँ—राष्ट्रपति श्री गिरि साहब का कहना है कि हमारे देश में बेरोजगारी में 10 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक लोग आते हैं। राष्ट्रपति जी जो बात लिखते हैं, वह सच्चाई की बात है, वे सरकार के मुखिया हैं, उनके आंकड़े जरूर सही होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि 100 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक लोग सेमी-एम्पलायड हैं—ऐसी हालत में, सभापति महोदय विडम्बना इस बात की है कि हम 450 रुपया टन के भाव से लोहा बाहर भेज रहे हैं। 900 रुपया टन का यहां पर कंट्रोल रेट है, परन्तु मैं अपना नाम बदल दूंगी, अगर कोई 900 रुपया टन के भाव में बाजार से लोहा ले तो आये, एक छटांक भी लोहा इस भाव में नहीं मिलता। 1600 रु० टन का इस वक्त कोटेड प्राइस है और 1600 रुपया टन पर भी नहीं मिलता है। मैं जानना चाहती हूं कि जब सीमेंट मंहगा हो गया है, वह मिलता नहीं है, लोहे की हालत यह है कि दो हजार रुपये टन भी वह नहीं मिल रहा है? तो क्या रोजगार मंत्रि मंडल के चेहरे को देख कर मिल जायेगा लोगों को? आखिर यह किसको धोखा दिया जा रहा है? यह जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है इसमें कोई शक नहीं कि यह सरकार की बात नहीं है, मुल्क के सामने एक सवाल हो गया है कि एक डेढ़ साल तक अगर यही समस्या रही तो फिर आपके बस की बात नहीं रह जायेगी, मुल्क को पटरी पर रखना मुश्किल हो जायेगा। आप सारी चीजों को बर्बाद कर देंगे। आप तो कुम्भकरण की नींद में सोये हुए हैं। कहते हैं कि जो कुम्भकरण की नींद में सोता है वह फिर उठता नहीं। खुशामद पसंद लोग इनको आँकड़े दे देते हैं और पार्लामेंट में उन्हीं का बयान हो जाता है। लेकिन उनसे इस मुल्क की हालत बदली नहीं जा सकती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब किसानों को उनके गल्ले का दाम नहीं मिलेगा, मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी और जो केन्द्रीय या राज्य कर्मचारी हैं उनको मंहगी चीजें खरीदनी होंगी तो वे कैसे खरीदेंगे? केन्द्रीय कर्मचारियों को अभी 106 करोड़ रुपया इन्टेरिम रिलीफ में दिया गया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यह हम नहीं लेंगे, हमको उचित रिलीफ मिलनी चाहिए। आखिर यह रिलीफ की मांग क्यों हो रही है? मुझे याद है, जब मैं कालेज में पढ़ती थी तो साढ़े 6 रुपये होस्टल चार्जेज थे जिसमें एक नाश्ता और दो खाने मिल जाते थे। उस समय वहां पर क्या जरूरत थी कि साढ़े 6 रुपये के बदले दस रुपये खर्च किये जाते?...(व्यवधान) ठीक है, तीन रुपये में भी मिल जाता था। उसी तरह से अगर आज मजदूरों को दो या तीन रुपये में आवश्यकता

की चीजें मिल जायें तो फिर और ज्यादा मांगने की क्या जरूरत होगी । भले ही फिलास्फर्स के लिए प्रोपगेंडा करने के लिए बात की बात निकालें और नारा लगायें लेकिन केवल नारों से ही रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, घर के ऊपर छत नहीं मिलती है और काम नहीं मिलता है या लोगों का इलाज नहीं हो जाता है । ये बुनियादी मांगे हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा । मैं कहना चाहती हूँ कि जब मंहगाई बढ़ती जायेगी, किसानों को गल्ले का दाम नहीं मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, केन्द्रीय कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिलेगा और फिर क्या केन्द्रीय कर्मचारी अपने बेटे हैं और राज्य कर्मचारी सौतेले बेटे है—यह कैसे हो सकता है ? केन्द्रीय कर्मचारियों को 106 करोड़ भत्ता मिला लेकिन उन्होंने कहा कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है । उनको जो कुछ मिला वह उनकी जेब में भी नहीं गया वह मंहगाई की देवी के पास चला गया और उनको कुछ मालूम भी नहीं हुआ । इसके बाद भी उनके सामने समस्या है क्योंकि 106 करोड़ से उनका काम नहीं चला । परन्तु आप बतायें कि जो केन्द्रीय कर्मचारी कलकत्ते में रहते हैं, पटना में रहते हैं, लखनऊ या चंडीगढ़ में रहते है वे मंहगी रोटी खरीदते हैं और वहां के राज्य कर्मचारी सस्ती रोटी खरीदते हैं, आखिर दोनों में फर्क कैसे हो सकता है ? जितनी मंहगी चीजें केन्द्रीय कर्मचारियों को खरीदनी पड़ती हैं उतनी ही मंहगी चीजें राज्य कर्मचारियों को भी खरीदनी पड़ती हैं । आज मुझे इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं है कि महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारियों ने यह मांग की कि उन्हें भी केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर ही मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए । पंजाब में भी यही मांग की गई । क्योंकि भत्ता उनकी परवरिश का एक रास्ता है, रुपया बनाने का कोई रास्ता नहीं है । तो जब आप मंहगाई खत्म नहीं करेंगे तब देश की सारी व्यवस्था उलट-पलट हो जायेगी और फिर बात आप के बस की नहीं रहेगी । आज इस समाजवादी छत्र-छाया में एक बहुत बड़ी विडम्बना यह देख रही हूँ कि खाद्यान्न के दाम गिर रहे हैं और बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं । आज कलकत्ता शहर में पहले के मुकाबले में 20 लाख लोग का रोजगार कम हो गया है । एक तरफ नक्सलवादियों की समस्या है । लोग आर्थिक विषमता से परेशान होकर उस रास्ते पर चले गये हैं जहां से उनको लौटाना मुश्किल है । वे खून बहाने के लिए तैयार हो गये हैं । क्योंकि उनकी जिन्दगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई है । उनके सामने वर्तमान और भविष्य की कोई तस्वीर नहीं रह गई है । वे समझते हैं कि हम तो जा ही रहे हैं । हम तो डूबे हैं सनम, तुम को भी ले डूबेंगे । यही दृष्टिकोण उनका हो गया है । परन्तु यह क्यों हो गया है ? एक तरफ तो काम नहीं है और दूसरी तरफ काम करने वाले नहीं हैं । एक तरफ तो कलकत्ता में उत्पादन नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पर बीस लाख आदमियों को जो काम मिला था वह कहीं पर लाकाउट, कहीं पर उत्पादन की कमी कहीं पर रा-मैटेरियल की कमी—इन सब कारणों से चला गया है ।

आखिर यह किस तरह की नीति है ? आखिर इन नारों से कब तक काम चलेगा ? खिलौने से कब तक बहलाया जायेगा ? नारे लगा लगा कर और बहाने बना बना कर किसी चीज को दबाया नहीं जा सकता है । धीरे-धीरे यह चीज एक दिन इस मुल्क में मासूर होकर फटेगी और फिर रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी । नारे लगाने वाले नारे लगाते रहें लेकिन मैं समझती हूं नारों के दिन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और इस सरकार को जाना हैं । विधाता किसी को लाठी से तो मारता नहीं बल्कि जब किसी को रुखसत करना होता

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है।...(व्यवधान)...तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक साल तक यह सरकार इस मुल्क को नारों से चलाती रही है लेकिन दूसरी ओर समस्यायें बढ़ रही हैं, उनका विकराल रूप हो रहा है। सरकार जाती है तो जाये क्योंकि इस सरकार के जाने का किसी को अफसोस नहीं होगा परन्तु इस मुल्क की सारी हस्ती चली जायेगी, इस देश की सारी मर्यादा चली जायेगी। आज इस सरकार की नीति को क्या कहा जाये? यह सरकार कहती है कि हमने अपना बैलेन्स बहुत बढ़ा लिया है, फारेन एक्सचेंज की कमाई बहुत कर ली है परन्तु मुल्क को यह बताती नहीं कि फारेन एक्सचेंज की कमाई इसलिए की है कि अपने यहां रा-मैटेरियल की कमी है, उसको यहां सप्लाई नहीं कर रही है और इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन के नाम पर इतना गोलमाल हो रहा है कि लोगों को उत्पादन करने के लिए फारेन एक्सचेंज नहीं दिया जायेगा और उसके लिए इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन का बहाना बनाया जायेगा। इस तरह से उत्पादन नहीं होगा।

मैं पंजाब और हरियाणा के मेम्बरों से पूछना चाहती हूं, जो इंडीकेट के मेम्बर्स हैं उनसे भी पूछना चाहती हूं क्या पंजाब के लोगों को पावर मिल रही है? बिजली मिल रही है? आज बिजली की हालत यह है कि दिन भर वह बन्द रहती है। हमारे रणधीर सिंह जी भी मानेंगे कि उनके खेतों में पानी नहीं जाता है।

श्री रणधीर सिंह : हर गांव में बिजली है, हर खेत में पानी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब सूखा हुआ खेत आपकी कांस्टीटुएन्सी में नजर आयेगा तो आपको दिखलाने के लिए ले चलूंगी।...(व्यवधान)...

तो मैं यह कह रही थी कि जब बिजली दिन भर बन्द रहेगी तो खेत में पानी कैसे पहुँचेगा? पंजाब में जो छोटे-छोटे उद्योगपति है उनके लिए बिजली नहीं, लोहा नहीं, सीमेंट नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, कुछ नहीं—वे लोग बेचारे धूनी रमा कर बैठे हुए हैं और सरकार के नारों को जप रहे हैं। लेकिन केवल नारों से लोहा और दूसरी चीजें नहीं मिल जायेंगी। इन हालात में उत्पादन कैसे होगा?

इसलिए मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि आज जो चीजें बिगड़ने लगी हैं उनको संजीदगी से रोकने की कोशिश की जाये। हम ने कहा कि योजना में उचित तरीके से परिवर्तन किया जाये। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था और उस वक्त जरूरत पड़ी थी तो हमने 600 करोड़ खर्च किया। उस समय मुल्क बैठा तो नहीं रहा? उस वक्त स्वाभिमान का प्रश्न था इसलिए वह खर्चा नागवार नहीं गुजरा। जब इस प्रकार की कोई बात देश के सामने होती है तो खर्चा करना ही पड़ता है। आज भी हमने कहा कि इस बेरोजगारी की समस्या को रोकने का एक ही तरीका है कि कुछ ऐसी स्कीमों को प्रायर्टी दी जाये जिनसे कि लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ रोजगार भी बढ़े। हमने कहा कि इस प्रकार का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। हमने कहा कि ट्यूबवैल्स लगाइये लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं लेकिन अगर ट्यूबवैल्स की मोटर खराब हो जाती है तो 6 महीने तक मिकैनिक की खुशामद करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि दिन में दस बार बिजली फेल होती है। ऐसी हालत में अगर मोटर खराब नहीं जायेगी तो क्या होगा। और जब मोटर खराब हो जाती है तो कोई उसको मरम्मत करने वाला ही नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर ट्रैक्टर खराब हो जाये तो उसको भी कोई मरम्मत करने वाला नहीं मिलेगा। हमने कहा कि ऐसी स्कीमें बनाइये जिनसे कि

सर्विसिंग के लिए गांवों में सुविधा रहे। वहां पर सड़कों की सुविधा हो और बिजली की सुविधा हो। एक पम्पिंग सेट में तीन महीने का समय लगता है और 6 महीने में फसल पैदा करके दे सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह के काम किये जायें तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो तमाम चीजों की खपत भी होगी और उससे लोगों को राहत पहुंचेगी। परन्तु आज तक इन बातों का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

दूसरी बात है कि यह सब क्यों होता है? चीनी की खपत बढ़ गई लेकिन उसके बाद चीनी के दाम भी गिर गये। चीनी इतनी पैदा हुई कि गन्ने को लेने वाला कोई नहीं। गन्ने वालों को अपना गन्ना जलाना पड़ा है। पिछले साल बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना चार आने मन भी नहीं बिका और लोगों को खेतों में गन्ना जलाना पड़ा चूंकि दूसरी फसल वे बोना चाहते थे और उसका वक्त आ गया था। यह सरकार इतनी निकम्मी है कि एक साल उपज ज्यादा हो गई चीनी की तो उसको रखने की भी इसके पास व्यवस्था नहीं थी। जब उपज ज्यादा होती है तो उसको रखने के लिए कोई इन्तजाम तो होना चाहिए। जब ऐसा इन्तजाम आप नहीं करते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि किसान बरबाद होंगे। यही हालात गल्ले के बारे में भी पैदा होने वाले हैं। बहुत शोर मचाया जाता है कि ज्यादा गल्ला पैदा किसान करें। मैं किसानों को मुबारिकबाद देती हूं कि उन्होंने गल्ला ज्यादा पैदा किया है। लेकिन कल या परसों उनकी क्या हालत होने वाली है, इसको भी आप देखें। आप देखेंगे कि किसी भी किसान के मुंह पर मुसकराहट आपको दिखाई नहीं देगी। गल्ला पैदा हुआ आंध्र प्रदेश में, पैडी, चावल या धान पैदा हुआ आंध्र प्रदेश में लेकिन उसकी कीमत काफी वहां गिर गई है। अब आंध्र प्रदेश वाले मांग कर रहे हैं कि जोनबन्दी को खत्म किया जाय। पहले उनकी मांग थी कि जोनबन्दी हो लेकिन अब उनकी मांग है कि इसको खत्म किया जाय। वे कहते हैं कि हम चावल भेजना चाहते हैं और इस जोनल सिस्टम को खत्म करें। लेकिन आज तक सरकार ने कोई अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया है। बिहार का गल्ला बिहार में सड़ जाएगा, हरियाणा का हरियाणा में सड़ जाएगा, पंजाब का पंजाब में सड़ जाएगा लेकिन यह सरकार कुम्भकर्णी नींद में सोई रहेगी। इसकी नीति में कोई परिवर्तन आ गया है, इसका पता नहीं चलता है। अगर यह जोन वाली नीति रहेगी तो उन का कोई रखवाला नहीं होगा, कोई राहत उनको नहीं मिलेगी। गल्ले को लेकर भी यहीं समस्या आपके सामने पैदा होने वाली है। उसका भी आपने बन्दोबस्त नहीं किया है। वेअरहाउसिंग आपके पास नहीं...

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पार्लियामेंट में आपको दिखाई देते होंगे। आंध्र में जा कर आप देखें, कितने वेअरहाउसिंग हैं। पार्लियामेंट में आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है। जिन का क्षेत्र सिर्फ पार्लियामेंट ही बन गया है और सिर्फ ट्रेशरी बेंचिज ही बन गया है, उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वर्ना आप ऐसी बात न कहते। वेअरहाउसिस नहीं हैं। अगर होते तो गल्ला क्यों सड़ता। हरियाणा में पिछले साल गेहूँ सड़ा क्यों? क्यों फूडग्रेंज कारपोरेशन को सड़ा हुआ गेहूँ खरीदना पड़ा? वर्मा जी जवाब दें। आपके पास वेअरहाउसिस की फैसिलिटीज होनी चाहियें। जितना उत्पादन बढ़ा है उसके मुताबिक होनी चाहियें, उससे ज्यादा होनी चाहियें। हमारे यहां बिहार में वेअरहाउसिंग की फैसिलिटीज नगण्य हैं। जो थोड़ी बहुत हैं, वे न के बराबर हैं।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

मैं समझती हूं कि यह जो उलट आ रहा है मार्किट में इसको देखते हुए सरकार एलान करे कि जोनबन्दी को खत्म किया जाता है। एक नई नीति सरकार तुरन्त अपनाए और जोन की जो सीमा है, उसको हटा दे।

आज लोगों ने चावल और गेहूं ज्यादा पैदा करना शुरू कर दिया है। वे स्विच ओवर हो गये हैं इस तरफ। कैश क्राप्स का प्रोडकशन उन्होंने कम कर दिया है जैसे तिलहन है, रुई है। उनको आपको विशेष इंसेंटिव देना चाहिये। आज आप देखें कि सरसों के दाम बहुत बढ़ गए हैं और वे घी के दाम के बराबर हो गये हैं। तिल के तेल और घी के दाम बराबर हो गए हैं। तिलहन की कमी है, रुई की कमी है। अभी सीजन आ रहा है। इसी सीजन में जो कैश क्राप्स प्रोड्यूस करते हैं उनको आप इंसेंटिव दें और उसका तुरन्त आप एलान करें।

आपने चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। ऐसा करके सरकार ने एलान किया था कि हम आर्थिक व्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स पर चले गये हैं। लगता है कि आप कैलाश पर पहुंच गये हैं, आपको जमीन दिखाई नहीं पड़ती है। कमांडिंग हाइट्स में जाने के बाद भी आज अर्थ व्यवस्था में प्रगति क्यों हो रही है, संतुलन क्यों नहीं है। सभी बड़े बड़े चौदह बैंकों का आपने राष्ट्रीयकरण कर लिया है। रिजर्व बैंक के पास इतनी पावर हैं कि वह अन्य बैंकों को भी कंट्रोल कर सकता है। क्यों नहीं आज बैंकों के द्वारा इंसेंटिव उन लोगों को दिये जाते हैं जो रॉ मेटीरियल पैदा करते हैं, कैश क्राप्स पैदा करते हैं? अगर देश में कमी है किसी चीज की तो उसको आप एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? स्टील की कमी है। आप डिक्लेयर करें कि स्टील का एक्सपोर्ट नहीं होगा और यहां के लोगों की जो स्टील की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, उनको स्टील दिया जायेगा। ऐसा आप करें तो छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलेंगे और यहां का जो उत्पादन है, उसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। बिजली की कमी है। आप कोशिश करें कि बिजली की कमी दूर हो और लोगों को बिजली सप्लाई हो। इससे उद्योग धंधों को चलाने में मदद मिलेगी। वनों पार्लियामेंट या सफदरजंग के चौराहों पर भाषणों से मुल्क को बहुत दिन तक बहकावे में रखा नहीं जा सकेगा। वह मुकाम आ रहा है जहां इसी सरकार को महसूस होगा कि यह गलती पर है।

सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में
मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही।

मैं सरकार को बतलाना चाहती हूं कि आज भी वह गलत काम कर रही है, गलत कदम उठा रही है। इस तरह से मंजिल कभी नहीं मिलेगा। हजूर गाह की तरह अभी तो आप बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री में लेकिन आप याद रखिये कि पार्लियामेंट तथा मुल्क की मर्यादा इखलाक, वफादारी और खलूस जिसने आपको मिनिस्ट्री दी है, उस सब को आप ले डूबेंगे। मुझे खतरा इसी बात का है। आप चले जायेंगे लेकिन आपके लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने साथ बहुत कुछ ले जाएंगे, इस बात का जरूर हमें अफसोस होगा।

एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आप ने आज आर्थिक व्यवस्था को लाकर खड़ा कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे उपाय करें ताकि यह हमारी आर्थिक व्यवस्था पटरी से गिरने न पाए। आप प्रगति की बात करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि प्लान में चार सौ करोड़ रुपये का कट हो रहा है। यह इसलिए करना पड़ रहा है कि लाली पौप की तरह आप पार्लिमेंट में स्कीमें एनाउंस कर देते हैं। आप कुछ लोगों को खुश करना चाहते हैं, एक बिरादरी, एक जाति, एक सम्प्रदाय, राज्य के एक क्षेत्र को खुश करना चाहते हैं। अब हालत यह है कि प्लानिंग कमिशन ने आपको कह दिया है कि

हमारे पास रिसोर्सिस नहीं हैं। आप रिसोर्सिस पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको प्लान में कटौती करनी पड़ रही है। साथ ही साथ यह भी मैंने सुना है कि 250 करोड़ रुपये का रेलवे में कट हो रहा है। जहां सही सलामत रेलों में सफर करने के लिए जगह नहीं मिलती है वहां ढाई सौ करोड़ के कट की बात चल रही है। ऐसी हालत पैदा हो जायेगी कि दिल्ली से पटना जाना चाहेंगे तो पटना भी नहीं पहुंच पाएंगे फिर चाहे मिनिस्टर कहीं से कहीं पहुँच जाएं। साधारण जनता उस अवस्था में नहीं पहुँच पाएगी।

मैंने यह भी सुना है कि चव्हाण साहब बड़ा जोर डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर कि चुनाव करवा लें। वह भुलभुलैया में फंस गये हैं कि इनफ्लेशनरी बजट पेश करें या डिफ्लेशनरी बजट। सुना है चूंकि महंगाई बढ़ रही है इसलिए डिफ्लेशनरी बजट पेश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मुल्क को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि जितनी भी योजनायें चल रही हैं, उन में कटौती होगी। इसलिए चव्हाण साहब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से चुनाव करवाइये ताकि जनता को यह पता न चले। अगर अब भी आप चुनाव करायें तो भी आपको महंगा सौदा पड़ेगा क्योंकि लोग कहेंगे कि चुनाव आप इसलिए करवा रहे हैं कि चुनाव के बाद आप लोगों का गला काटेंगे, टैक्स पर टैक्स उन पर लगाएं। डिवेलेपमेंट स्कीमें सब आप रोकेंगे तो भी उसका खराब असर पड़ेगा। इसलिए किसी भी तरह सस्ता सौदा यह नहीं रहेगा। जहां भी जाएंगे और जब भी जाएंगे चुनाव के लिए महंगा सौदा ही होगा। आपकी हालत सांप छछूंदर की हो गई है। न निगलते बनता है और न ही उगलते बनता है। उस आर्थिक व्यवस्था में आपने देश को फंसा दिया है।

आज भी वक्त है कि आप सरकारों को गिराने के बजाय, डिफैकशंज कराने के बजाय देश की आर्थिक अवस्था को सुधारें और उस में लग जायं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश का कल्याण नहीं होगा।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): There can be no two opinions that prices have risen and are rising, but to lay the entire blame on the Government would be going a little too far. There are many reasons why the prices have risen and there is a lot of suffering especially in the fixed income groups and in the salaried groups People with fixed incomes have to pay a higher price for the same things but as their salaries and wages have not risen, they have to take lesser quantities and forego certain essential necessities of life.

It is also a fact that production has risen in every sphere. For example production in the agricultural sector has gone up during the period 1952 to 1970 by 50 million tonnes.

Yet, there is a shortage of agricultural goods; there is a rise in the prices of agricultural produce also. Now, the question arises why there is this rise in prices in every sector. One of the learned Members said in the House that the main cause for the rise in prices is deficit financing. Probably my hon. friend is not aware that it is necessary for a country whose economy is a developing economy, to go in for deficit financing.

I will give an example. If there are 100 tonnes of steel being produced, and the money in circulation is only Rs. 100, then one tonne would be purchased for one rupee, but if the production goes to 200 tonnes and the circulation of money remains at Rs. 100, the price per tonne will come down to eight annas. The result would be that the factories which are producing steel would run in a loss and they will close down. Secondly, to make up for the loss, it is necessary and it has been accepted by all the countries in the world and by all economists, that when there is a rise in production you must also inject money in the economy. That is, it is necessary to go in for deficit financing, when production is going up, so as to keep employment going up to increase production. Therefore, if one says that there should never be deficit financing, probably one has very little knowledge of economics and one is not trying to grapple with the realities. Therefore, it is wrong when Members say that

[Shri Vikram Chand Mahajan]

the entire rise in price is because there is deficit financing and that therefore the Government should stop deficit financing. For every developing country and a developing economy, deficit financing is necessary. So far as the present Government is concerned, they have correctly and to the extent to which it is necessary resorted to deficit financing.

Another hon. Member said the other day, when the debate was on, that the Government is giving support prices to agricultural produce, and that is causing a rise in prices also. My hon. friend that day forgot that if you want a farmer also to reap the results of his efforts, the efforts which he puts in producing whatever he can produce, then he must also have a guarantee that he will get the necessary price for what he is producing. If a farmer does not get what he is entitled to the next time, firstly he will go into bankruptcy and secondly, the nation would also lose in production because he will not produce that much of goods, and so it is necessary for an agricultural country like India to give support prices for agricultural produce, and that is why I think Mrs. Tarkeshwari Sinha was correct when she said that the Government should always give support prices to agricultural produce.

Not only this. The Government should make it as a matter of policy that wherever there is more production it should go in for buying the ensure surplus produce of that region, so that price do not fall there and the farmers have enough return for what they produce.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : What about the consumer ?

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Our great leader asks, what about the consumer. Let us see who is the consumer. The consumers are the people who inhabit this country. 80 per cent of the population lives on land and 20 per cent does not live on land. Basically, the consumer is that 80 percent, and if 80 percent does not get enough for what it produces, what is he going to consume ? It is true that so far as the industrial sector is concerned, so far as labour is concerned, they should get the necessaries of life at a fair price, but that is no ground for giving to the 80 per cent of the population prices which will put them into bankruptcy. For the last 100 years the agricultural sector has not been ignored and it has not been given enough price to which it is entitled to.

All the economists of India are agreed that the present price is not remunerative for the agriculturists and it should be higher. That is the consensus of opinion of the economists in India as well as in other countries. That is why in countries like USA and Canada, the Government purchases the entire farm production at a higher price and sells it at a loss, at a subsidised price to the consumers, because there they know that if they want the farmers to make both ends meet, they should give them a fair price. The same thing should be done in India also. When Acharya Kripalani asked, "what about the consumer", he was referring to consumers working in the factories, *i.e.* labourers. For that, the answer is, the Government should subsidise the necessities of life so far as labour is concerned. For fixed income groups, Government should sell in fair-price shops at subsidies prices, whatever the labour in a particular region consumers, whether it is corn, wheat or rice. In industrial sectors, it is the dut of the owners of the industries to run fair-price shops. This has already been started in many sectors in Kanpur and Calcutta and in places where Government are running industries.

SHRI J. B. KRIPALANI : So, there is no problem ?

SHRI VIK AM CHAND MAHAJAN : There is a problem. Wherever there is a lacuna, Government should enter. Many State Governments have started doing it. In Delhi also, labour can buy foodstuffs at fair-price shops, though Government loses money. That should be the policy of a Welfare State which believes in socialism and our Government is doing it.

Then, why are prices rising ? The answer is two fold. It cannot be denied that production has gone up in every field. In 1952, farm production was only 52 million. In 1970 it is 100 million tonnes. Yet, we have to import food because food production has not kept pace with population growth.

SHRI J. B. KRIPALANI : You say food production has gone up by 100 per cent from 52 to 100 million tonnes. Do you mean to say population has grown 100 per cent in this period.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : We are importing less food in 1970 than we did in 1952, though the population has gone up by 75 per cent. In 1947, the population of United India was 40 crores.

At present the population of India alone is 55 crores. This clearly shows that the main reason why the prices are rising is that the population in our country has outstepped food production and set at nought our entire planning. So, the main problem before us is to check the population. The time has come when Parliament as a whole irrespective of party affiliations, should recommend compulsory family planning in this country.

Secondly, there is accumulation of black money in the hands of a certain section. That black money is not used in production but only in purchasing consumer goods. The reason is this. If it is to be used in production it will have to be shown in books of accounts and there will be difficulty about income-tax. The income-tax officer will ask how this money was earned because the statements of income of previous years will not show that income. In order to avoid all this they go on a spending spree. The best way to meet this problem is to demonatise the present currency. That will bring out the entire money into the market. That will be a restraint on rising prices.

Thirdly, so far as the fixed income group is concerned, their necessities of life should be subsidized, as is done in advanced countries.

SHRI J. B KRIPALANI : The Rashtrapathi and the Governors come in the salaried group.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Then I will modify it as lower income group.

Lastly, Governmental expenditure should be cut down. There can be no two opinions that the expenditure on bureaucracy is rising. We should reduce it wherever there is scope.

I conclude by thanking you for giving me this opportunity.

SHRI PREM CHAND VERMA : I beg to move :

"That is the amendment to the Resolution moved by Shri Bhibuti Mishra printed as S. No. 8 of amendments in List No. 3, –

(1) in part (i), between "recent" and "trend" *insert* "rising"

(2) in part (ii),—

omit "and the measures already taken by the Government to check the "trend" (9)

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : श्रीमान्, यहां महंगाई की चर्चा जब होती है तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि देश में औद्योगिक वस्तुओं के दाम बहुत अधिक नहीं बढ़ने चाहिए । परन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि देश की जिस जनता का ध्यान इस विषय पर चर्चा करते हुए होना चाहिये उसका उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है । अगर इस देश को कहें कि यह कहां बसता है, तो कहा जायगा यह देश गांवों में बसता है क्योंकि 82 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है । अगर इस देश में कोई व्यवसाय या पेशा है जिसमें सबसे अधिक आबादी लगी हुई है तो वह खेती का पेशा है जिसमें 70 फीसदी से अधिक आदमी लगे हुए हैं । मेरे बहुत से साथियों ने बताया कि महंगाई बढ़ते वक्त यह ध्यान नहीं रखा जाता कि किसान को भी उसका उचित मूल्य मिले । मैंने भी इसी प्रकार का संशोधन यहां सदन में प्रस्तुत किया है । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान के साथ और उसके उत्पादन के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है । इसी पिछले 10 नवम्बर को राज्य सभा में हमारे वित्त मन्त्री श्री चव्हाण ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे और उन आंकड़ों में उन्होंने कहा था कि हमारा थोक मूल्यों का जो सूचकांक है वह अक्तूबर 1969 से अक्तूबर 1970 तक 6.8 प्रतिशत बढ़ गया और औद्योगिक उत्पादन का मूल्य इसी अवधि में 7-8 परसेंट बढ़ गया ।

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

लेकिन खाद्यान्न का जो मूल्य है वह 5 कम हो गया। यानी जहां और चीजों का औद्योगिक उत्पादन का और थोक चीजों का मूल्य सात आठ प्वाइन्ट बढ़ा है वहां कृषि उत्पादन का मूल्य प्वाइन्ट आठ कम हो गया।

इसी तरह से दूसरी बात और भी आंख खोलने वाली है। सन् 1968-69 में गुड़ का भाव 86 रुपये प्रति क्विंटल था और अगले साल 1970 के अप्रैल में 45 रुपये प्रति क्विंटल रह गया, यानी भाव आधा रह गया। इसी तरह से खांडसारी का भाव अप्रैल 1969 में 205 रुपये प्रति क्विंटल था और अप्रैल 1970 में 110 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। यानी भाव आधा रह गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे ज्यादा किसान के साथ क्या ज्यादती हो सकती है कि एक साल पहले उसकी चीजों का भाव जितना हो वह अगले साल उससे आधा गिर जाय। तो इससे ज्यादा अन्याय किसान के साथ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा ज्यादती उसके साथ और नहीं हो सकती।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक महंगाई का सवाल है महंगाई और सबसे ज्यादा किसी को परेशान करती है, महंगाई का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर होता है तो वह गांव के आदमी पर होता है। मिसाल के तौर पर एक शहर के आदमी को अपने बच्चे को पढ़ाना है और एक गांव के आदमी को अपने बच्चे को शिक्षा देनी है तो शहर का आदमी शहर में रहकर जितनी सस्ती शिक्षा अपने बच्चे को दिला सकता है, गांव के आदमी को अपने बालक को उतनी शिक्षा दिलाने के लिए उससे तीन गुना चार गुना अधिक खर्च करना पड़ता है। तो जब महंगाई आती है तो गांव के आदमियों पर ज्यादा उसका असर पड़ता है। इसी तरह से भवन निर्माण की सामग्री है। भवन निर्माण की सामग्री शहरों में सस्ती मिलती है और गांवों की मिसाल में आप को बता दूं कि यहां से बदरपुर में भवन निर्माण की सामग्री ले जाऊं तो जैसे गांव से भूसा लाने के लिए उतनी कीमत भूसे की नहीं देनी पड़ती जितनी कि उसके ट्रांसपोर्ट को देनी पड़ती है, बिलकुल ठीक इसी तरह से यहां से बदरपुर ले जाने के लिये जितनी कीमत सामान की नहीं होगी उससे दुगुनी बदरपुर ले जाने के लिए ट्रक की कीमत देनी पड़ती है। तो भवन निर्माण की सामग्री भी वहां महंगी पड़ती है। मेरा यह दावा है कि शहर की अपेक्षा गांव वाले महंगाई से ज्यादा सताए जाते हैं और उन्हें दोहरी मार पड़ती है। उनके उत्पादन का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है और उनको जो बाजार से चीजें खरीदनी पड़ती हैं वह बहुत ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ती हैं। मैं जो देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस देश के आर्थिक ढांचे को बनाए रखना है, इस देश के कारखाने को, बाजारों को और शहरों को बसाए रखना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति को, उनकी परचेजिंग पावर को बनाए रखना होगा। अगर गांव के आदमी की क्रय शक्ति कम हो गई यानी उसको अपनी कमाई का और अपने उत्पादन का मूल्य कम मिला तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जायगी और जब उसकी क्रय शक्ति कम हो जायगी तो आपके कारखानों का उत्पादन, आप का औद्योगिक उत्पादन और आप की दूसरी सारी चीजें जो हैं वह एकदम ठप हो जायेगी। इसलिए अगर आपको अपना आर्थिक ढांचा खड़ा रखना है। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो गांव के आदमी की क्रय शक्ति है वह आपको बनाए रखनी चाहिए। यहां क्या तमाशा होता है कि मान लीजिए कि महंगाई बढ़ी तो आवाज उठती है कि सरकारी कर्म-

चारियों का वेतन और भत्ता बढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ना चाहिए। मजदूरों के लिए आवाज उठती है कि महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, ठीक है बढ़ना चाहिए। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उनकी मांगें भी बढ़ती जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनके वेतन और भत्ते बढ़ते जाते हैं। लेकिन गांव का आदमी किस के पास जाय? अगर उसको महंगाई का मुकाबिला करना पड़ता है तो उसके लिए क्या उपाय आपने रखा है? सरकारी कर्मचारी ठीक है कि उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह बात भी माननी पड़ेगी कि वह अनप्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं, अनुत्पादक काम में लगे हुए हैं और जो उत्पादक काम में लगा हुआ है उस उत्पादक काम में लगे हुए आदमी के लिए महंगाई बढ़ती है, महंगाई से उसकी कमर टूटती है तो उस 75-80 फीसदी जनता की कोई सुनने वाला नहीं है जबकि इनकी मांगों के लिए अखबारों में भी आता है, रेडियो पर भी आता है, प्लेटफार्मों पर भी बात होती है और पार्लियामेंट में भी बात होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह सरकार या आर्थिक नीति निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार लोग या राजनीतिक लोग हमेशा यह चिंता रखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से परेशानी न उठानी पड़े, जितनी महंगाई बढ़े उसी तरह से उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ती रहे, ठीक इसी तरह से हमको यत्न करना चाहिए कि किसान की क्रय शक्ति भी बढ़ती रहे जैसे-जैसे चीजों के दाम ऊपर उठते रहें, उसकी जो परचेजिंग पावर है वह भी हमें बढ़ानी चाहिए। हमारा यह कैसा समाजवाद है—हम आर्थिक नीतियों की चर्चा करते हैं, अन्य बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन जो 80-82 फीसदी आदमी गांवों में रहता है, उसकी तरफ हमारा ख्याल भी नहीं है।

अभी हमारे एक समाजवादी सदस्य बोले, अच्छा होता वे इस समय सदन में होते, उन्होंने सुझाव दिया कि गांवों की सारी जमीन को छीन कर इकट्ठा कर देना चाहिये। जो लोग खेती करने वाले हैं वे जानते हैं कि यह कितना अव्यवहार्य सुझाव है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो लोग ऐसे सुझाव देते हैं उनके सामने एक विचारधारा है। जिस तरह से वे लोग कारखानों में जाकर हड़तालें कराते हैं, ठीक उसी तरह से वे गांवों में भी जाकर हड़तालें कराना चाहते हैं और गांवों में तब तक हड़ताल नहीं हो सकती, जब तक गांव का आदमी मजदूर नहीं बन जाता। इनके सुझाव के अनुसार जब वह मजदूर बन जायगा, तब ये नेता लोग वहां जायेंगे और कहेंगे कि तुम को यह नहीं मिलता है, वह नहीं मिलता है, इस लिये हड़ताल करो, गेहूं मत बोओ, हम तुमको लेकर दे देते हैं। ये राजनीतिक पेशेवर लोग समझते हैं कि हम कारखानों में घुस चुके हैं, सरकारी दफतरों में घुस चुके हैं, अगर इनको कहीं प्रवेश नहीं मिला है तो वह खेतों में नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर किसान ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से अपने पेट को भर रहा है, इसलिए वहां भी इनकी नजर है और उसका नतीजा यह होनेवाला है कि हमारे ये नेता लोग वहां भी लाल झण्डी लेकर पहुंच जायेंगे और हड़ताल का नारा लगायेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के अव्यवहार्य सुझाव राजनीतिक दृष्टि से तो दिये जा सकते हैं, इलैक्शन की दृष्टि से दिये जा सकते हैं, जिन लोगों से पैसा लिया जाता है, चन्दा लिया जाता है, उनके लिये ठीक है, लेकिन गांव के आदमी की दृष्टि से जो खेती करता है उसके मन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिसका खेती से जरा सा भी सम्बन्ध है, जिसने कभी खेती देखी है और जो देश के प्रति ईमानदार है, वह आदमी कभी भी इस तरह के सुझाव नहीं दे सकता।

16.53 hrs.

[Shri Prakash Vir Shashtri *in the Chair*]

यह ठीक है कि आप ऐसे तरीके अपनायें

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

जिससे महंगाई न बढ़े, महंगाई जितनी बढ़ेगी, आम आदमी उतना ही परेशान होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान आपको इस बात का रखना होगा कि कृषि उत्पादन का उचित मूल्य किसान को मिले, जिससे उत्पादन के प्रति किसान का उत्साह बढे, उसको विन्वास हो कि उसके साथ न्याय हो रहा है, आज देश में अमुक चीज की कमी है, हमको अमुक चीज पैदा करनी है। लेकिन यहाँ होता क्या है—जैसा मैंने पहले कहां—एक दफा नारा लगता है कि चीनी की कमी है, किसान ने गन्ना बोया जब चीनी का उत्पादन बढ़ गया तो मन्त्री महोदय कहते हैं—देखिये साहब, इतना गन्ना पैदा होने लगा है, चीनी इतनी ज्यादा पैदा हो गई है कि मूल्य का स्तर कैसे कायम रह सकता है। उसके बाद कहा गया कि गेहूँ बोओ—किसान ने बहुत बड़ी मात्रा में गेहूँ पैदा किया। अब कहने लगे कि गेहूँ इतना ज्यादा पैदा हो गया है कि हम कहां से इतना दाम दे सकते हैं। अन्य चीजों की जिम्मेदारी लेने को यह सरकार तैयार है, लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी लेने को सरकार तैयार नहीं है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आप को मालूम है कि पिछले साल किसानों के खेतों में कितना गन्ना जलाया गया और इस साल कितना गन्ना किसानों के खेतों में खड़ा हुआ है, जिसको कोई लेने को तैयार नहीं है—क्या सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं ले सकती कि उसके गन्ने को उचित दामों पर खरीदवाये, लेकिन यह सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। यहां आकर कह देते हैं कि हम मिलों को नहीं कह सकते हैं, फिर यह सरकार यहां पर क्यों बैठी हुई है। अगर बैठे हुए हैं तो आपको यह जिम्मेदारी लेनी होगी।

इसलिए मेरा सरकार से और जो देश की अर्थ नीति का निर्धारण करने वाले लोग हैं—उनसे अनुरोध है कि जब तक वे किसान और गांवों का जो आर्थिक ढांचा है, वहां का जो कृषि उत्पादन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसको उचित मूल्य नहीं देंगे, उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, तब तक आप देश के आर्थिक ढांचे को ऊपर-ऊपर हवाई तौर पर चला नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा संशोधन है कि बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जाय, कृषि उत्पादन के मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जाय और किसानों को आश्वासन दिया जाय कि अगर औद्योगिक उत्पादन की वस्तुओं को किसानों को महंगा खरीदना पड़ा तो किसानों की पैदावार के दाम भी उसी अनुपात से बढ़ाये जायेंगे। अगर आप यह आश्वासन दे सकेंगे तब तो देश में कृषि उत्पादन बढेगा, अन्यथा आपका यह आर्थिक ढांचा नहीं चल सकेगा।

SHRI A. C. GEORGE (Mukundapuram): Sir, in my opinion, the resolution and the discussion here have been brought at a very correct time. This is the time when the Government machinery must be geared to its optimum efficiency.

Sir, the cost of living index is shooting up like anything and I think one of these days the graph is so steep that it may even jump off the graph paper supplied by the Bureau of statistics.

The rise in prices mostly affects the poor people. Of course, it is true that the people are feeling more conscious of their wants, but that is not a consolation. Also I do not want to be consoled by the fact that even in Poland where there is very strictly restricted economy, there are riots because of the 20% rise in prices of food articles. That is not going to console us. We are concerned mostly with what is happening in our country.

Many people are saying and criticising that the workers are demanding more wages and they are resorting to strike. Of course, I am one who does not support strikes which are politically motivated. But, if we just look at the present situation, what is left to the workers? Every day he is feeling that his stomach is empty and his wants are not met.

The other day we read and in fact there was a question put in this House itself that

foodgrains, especially paddy, are rotting in Punjab for want of enough railway wagons. At the same time, back home in my State of Kerala, the rice price is going up beyond the means of the ordinary worker and this is all due to wrong planning and due to improper staggering of the vehicle allotment, grains are getting rotten in Punjab while the poor people of Kerala are suffering for want of rice. This anomalous situation has arisen simply because of wrong planning, I may submit. Here, the Government machinery should move in with the greatest efficiency. There is absolutely no doubt about it.

Another aspect which is coming up to the forefront is that while the essential commodities prices are going up, in Kerala State the prices of cash crops are, going down, especially of rubber, cardamom and other staple products of the Kerala State. The middlemen, the traders are pushing down the prices of rubber. The big tyre factories and the rubber dealers are purposely keeping away from the market to push down the prices. At the same time, the price of tyre is going up. Sir, this is an artificial situation created by the monopolists and there is absolutely no doubt about it. Sir, the Government must step-in in a big way.

Sir, the purchasing capacity of the worker's salary is going down day by day. I may submit that in Andhra 83% of the rice mills are controlled by 23 big mill-owners. During the farming season these big money-lenders offer a pittance to these poor farmers at a very high interest and during the harvest season, the entire crop is taken away, almost commandeered, by the mill owners and they hoard it and ultimately, while the Andhra farmer is not getting the proper price for his product, the consumer in Kerala is getting it at a very high price. So I put a demand before you that it is high time that the Government step-in in the processing industries.

Basic commodities should be made available to the workers and the ordinary people at the lowest price possible. Here, I may add that it is high time that the Government think about the suggestion of giving a part of the salary of the workers in kind, Their basic necessities and the consumer goods must be supplied at subsidised rates and part of the wages must be given that way. In fact, that, to a great extent, I believe, will relieve the workers of the present burden of the rising prices.

17.00 hrs.

Sir, in the urban areas in Kerala, a serious situation is coming up. Half the salary which the workers receive is being paid only for rent. The Government does not have the imagination to build sufficient number of houses. If only the nationalised banks apportion a good amount of their deposits for housing schemes and construct houses, the real wages of the railway employees, the Government employees, the teachers and the factory workers will go up to that extent. Now, I know of instances where the salaried people, getting Rs. 250 per month are paying Rs. 80 or Rs 90 by way of rent alone. What is left ? Barely Rs. 160 or so. Normally, according to the economists, 10 per cent is the quantum fixed for rent. But, in effect, they really pay more than 40 or 50 per cent of their salary on rent alone. It is time Government step-in and do housing construction and give them housing facilities at 10 per cent of their salaries. That will to a great extent help in solving this particular problem and the real wages also will go up.

On this occasion, I would like to bring one suggestion to the notice of the Government of India and it is this. From now on, it is high time that we put a ban on residential buildings costing more than Rs. 1 lakh. No rich man—whatever be his economic position—has a right in India, hereafter, to build residential houses and palaces worth more than Rs. 1 lakh. This money must definitely be converted to produce ordinary house constructions for the ordinary poor people, the salaried people and the wage-earners. I am really apprehensive that this particular problem has not come to the notice of the Government in all its real perspective.

In Delhi for instance, there are so many people who speak for the higher wages of the Delhi workers and for the Government employees and all that. But, I am afraid they are not putting enough pressure upon the Government, focussing the attention of the Government to this particular problem. A Class IV or Class III person pays Rs. 100 nearly on rent alone, amounting to 30 or 35 per cent or even 40 per cent of his salary and this situation must be remedied. I hope Government will pay greater attention to this Housing problem. I hope and trust that

[Shri A C. George]

Government will consider my suggestion seriously—namely, to put a ceiling on residential buildings costing more than Rs. 1 lakh.

Sir, regarding the cash crops in Kerala, the farmers and the agriculturists are completely at the mercy of the speculators and the middlemen. It is high time the processing industries are taken over by the Government. Rice hulling and big flour mills must be controlled by the Government, so that, this particular sector of our economy will come in the hands of the Government of India.

Once again stressing the need for more housing schemes, may I, in conclusion, say that a sizeable portion of the salary must be paid in kind, basic materials, to the employees ?

I hope and trust that Government will seriously think over my suggestions and put a ceiling on residential buildings and see that no residential buildings costing more than Rs. 1 lakh can be built hereafter. Thank you.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, आजादी के कई साल बाद आज भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जिसकी तुलना उस स्थिति से की जा सकती है जो स्थिति जर्मनी में हिटलर के पावर में आने के पहले थी या जो स्थिति चीन में माओत्सेतुंग के पावर में आने के पहले थी । च्यांगकाईशेक के जमाने में चीन में और बीमार रिपब्लिक के जमाने में जर्मनी में कीमतें लगातार चढ़ रही थीं और रुपये की कीमत, चीन में युवान और जर्मनी में मार्क की कीमत लगातार गिर रही थी उसके कारण वहां पर जो कामन मैन, आम आदमी थे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे किसी प्रकार के चेंज को भी स्वागत करने के लिए तैयार थे । आज वही स्थिति भारत में होती जा रही है । जितने ही नारे यहां पर समाजवाद के लगाये जाते हैं उतनी ही हालत यहां पर कामन मैन की बिगड़ती जा रही है । आदमी को याद आता है मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । कारण स्पष्ट है । कीमतें बढ़ने की जो बीमारी है उसका इलाज सभी चाहते हैं कि होना चाहिए मगर किसी बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बीमारी की तश्खीश न की जाये, उसका निदान न किया जाये, उस को डायग्नोज न किया जाए । लेकिन हमारी सरकार बीमारी को डायग्नोज करने के लिये तैयार नहीं है । मेरा कहना है कि इस देश के अन्दर कीमतें बढ़ने का सब से बड़ा कारण है समाजवाद । समाजवाद कीमतें बढ़ाने का मानो एक साधन है । समाजवाद के नाम पर यहां पर आर्थिक ढांचे के ऊपर सरकार का शिकंजा बढ़ रहा है । जहां पर भी सरकार पहुंचती है वहां पर कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ।

पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी का मेम्बर होने के नाते मुझे विभिन्न पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को देखने का मौका मिला है । जो प्राइवेट इदारे हैं उनको भी देखने का मुझे मौका मिला है । आपको जानकर अचम्भा होगा कि जो प्राइवेट बिजनेस हाउसेज है, जब उन्हें पता लगता है कि जिस इंडस्ट्री में वे है उस इन्डस्ट्री में पब्लिक सेक्टर का कारखाना खुल रहा है तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं । उनमें से एक ने हमें बताया कि इससे एक बात निश्चित होती है कि गवर्नमेंट कीमतें तय करेगी अपने पब्लिक सेक्टर के कारखाने की कास्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर और वह जो कास्ट आफ प्रोडक्शन होगी वह हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम से कम दस परसेंट ज्यादा होगी इसलिए दस परसेंट का प्राफिट उनको घर बैठे मिल जायेगा लेकिन यह जो कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती है उसका बोझ किस पर पड़ता है ? उसका बोझ कीमतें बढ़ा कर कंज्यूमर्स पर पड़ता है फिर जिस ढंग से सरकार लोगों से रुपया लेती है, पूंजीपतियों से और कारखाने वालों से, किसी से एक करोड़ चुनाव फंड में लेती है तो उसको दस करोड़ की छूट देती है कीमतें बढ़ाने के

लिए और उसका सारा बोझ कंज्यूमर्स पर जा कर पड़ता है। तो यह जो समाजवाद के नाम पर जो स्टेट की मनोपली कायम की जा रही है, यह स्टेटीज्म जो आ रही है इस देश में वह सब से अधिक घातक है कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स का लाभ होता है कम्प्टीशन में। हमारे सामने इण्डियन एयर लाइन्स का मामला है, वहां पर क्यों हालत इतनी बिगड़ गई है? पिछले दिनों एयर इन्डिया को हम एग्जामिन कर रहे थे। उनके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आये थे। उनसे हमने पूछा कि हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में यह सबसे अच्छी है, दुनिया भर में इसका नाम है ऐयर इंडिया का और यह शुरू से नफा निकाल रही है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? तो उनके चेयरमैन ने जो कहा वह हमारे रिकार्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण यह है—कि We have to face a very stiff international competition. We cannot exist unless we are efficient and unless we are economical.

वहां चूंकि मानोपली नहीं है बल्कि कम्प्टीशन है इसलिए एयर इण्डिया प्राफिट निकालती है और दुनिया के अन्दर नाम भी कमाती है। लेकिन जहां पर मानोपली कायम कर दी जाती है वहां पर यह सम्भव नहीं रह जाता है। कहीं कहीं पर प्राइवेट मानोपली भी बढ़ी है लेकिन प्राइवेट मानोपली का मुकाबला किया जा सकता है, उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसपर रोक लगाई जा जा सकती है लेकिन जब स्टेट की मानोपली हो, स्टेट के पास पुलिस की पावर है, मिलिट्री की पावर है और जब उसके साथ आर्थिक सत्ता भी जुड़ जाती है तो स्टेट एक शैतान बन जाती है और फिर उस शैतान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। यहां पर भी स्टेट एक शैतान बनती जा रही है कामन मैन को खाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह समाजवाद के नारे जो हैं, समाजवाद की नीतियां जो हैं, कोई भी बताये कि आप के इस समाजवाद की नीति से कामन मैन का भला हुआ है?

अभी मेरे भाई हाउसिंग की बात कर रहे थे। हमने पिछले कई सालों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपया डेवलपमेंट पर खर्च किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस 30 हजार करोड़ में से कितना रुपया हाउसिंग पर खर्च किया गया है? दिल्ली के अन्दर 15 सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि चार पांच करोड़ रुपया दे दो लोन की शक्ल में ही, हम इसका एक रिवाल्विंग फंड बनायेंगे, उससे मकान बनायेंगे जो कि हायर पर्चेज के आधार पर देंगे और उससे जो रुपया आयेगा उससे और मकान बनायेंगे। दिल्ली में अरबों रुपया बड़े-बड़े महलों को बनाने पर खर्च किया गया है, प्रधान मंत्री का एक नया महल बनने जा रहा है लेकिन दिल्ली के कामन मैन के लिये दो दो कमरे के छोटे छोटे मकान बन सकें उसके लिए पांच करोड़ रुपए का लोन भी नहीं मिल सकता है ताकि एक रिवाल्विंग फंड ही बनाया जा सके। इस सरकार के हाथी के दांत हैं—खाने के और, दिखाने के और। बातें समाजवाद की लेकिन काम सामंतवाद और पूंजीवाद के। कारण स्पष्ट है। कहा जाता है कि मानोपोली बढ़ गई है, कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक सत्ता केन्द्रित हो गई हैं। इस देश में पिछले 23 साल में सत्ता किसके हाथ में रही है। पहले सत्ता जवाहर लाल के हाथ में थी। बीच में अठारह महीने लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। फिर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सत्ता नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी के हाथ में आ गई।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। क्या आप इसकी इजाजत देंगे कि कहा जाये कि हत्या कर दी गई? क्या यह रिकार्ड पर रहेगा? मैं अपील करता हूं कि इसको एक्सपंज कर दिया जाये। जब तक

[श्री मु० अ० खां]

यह साबित नहीं हो जाता है कि हत्या करवा दी गई है, तब तक इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप का विरोध लिख लिया गया है।

श्री बलराज मधोक : सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। इन्होंने डा० श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या करवाई, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई। यह घातकों की सरकार है, नर संहार करने वाली सरकार है। यह मेरा इस सरकार के ऊपर चार्ज है।

श्री रणधीर सिंह : बहुत गलत बात है। क्या ताल्लुक है इस सब का मौजूदा बहस से। मधोक जी जैसे आदमी इस तरह की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है।

श्री बलराज मधोक : इस देश में गांधी जी की हत्या हुई। उसके बारे में एक ट्रिब्यूनल बैठा और उसने फैसला दिया। बीस साल के बाद नई इनक्वायरी हुई। नेता जी के लापता होने के बाद फिर बीस साल के बाद इनक्वायरी दुबारा हो रही है। डा० मुखर्जी की हत्या की गई, कोई अभी तक उसके बारे में इंक्वायरी हुई? लाल बहादुर जी के बारे में इनक्वायरी की मांग हो रही है। दीन दयाल उपाध्यक्ष जी की हत्या की गई, उसके बारे में लीपा पोती की जा रही है। जब तक यह सिद्ध नहीं होता है इनक्वायरी के बाद कि लाल बहादुर जी की मृत्यु नैचुरल काजिज की वजह से हुई, तब हमें यह कहने का अधिकार है कि उनकी हत्या की गई। जब यह तय हो जायेगा इनक्वायरी के बाद कि वह नैचुरल डैथ थी, तब हम यह बात नहीं कहेंगे।

सभापति महोदय : इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री बलराज मधोक : मैं कहना चाहता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अभी उन्होंने कहा कि नेता जी की हत्या हुई। क्या यह सही नहीं है कि खुद उन्होंने इनक्वायरी के ऊपर दस्तखत किए थे? बहुत से लोग भारत में विश्वास करते हैं कि नेता जी जीवित हैं। इस वास्ते इनक्वायरी हो रही है।

श्री बलराज मधोक : अठारह महीने लाल बहादुर जी सत्ता में रहे। इस अर्से को छोड़ कर सत्ता लगातार एक परिवार के हाथ में केन्द्रित रही है। इस लिए देश में जो आर्थिक दुर्व्यवस्था है, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, उस सब की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अगर आती है तो जवाहरलाल जी पर आती है या इन की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर आती है।

श्री मुत्याल राव (नगरकुरूनल) : जवाहर लाल जी पर बिल्कुल नहीं आ सकती है।

श्री बलराज मधोक : जो बीमारी है उस का पता लगा कर उसका इलाज ढूंढने का प्रयत्न होना चाहिए। बीमारी क्या है? बीमारी यह है कि हमारी आर्थिक नीतियां पहले दिन ही अव्यावहारिक थीं, उनको बनाने वाले वे लोग थे जिनका भारत से कोई वास्ता नहीं था वे रूस से बहुत अधिक प्रेरित थे। अगर इस देश की आर्थिक नीति बनाने वाले किसान के बेटे होते, सरदार पटेल होते तो आप देखते हमारी आर्थिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ होती। सरदार पटेल के पिता एक बहुत छोटे किसान थे। दस एकड़ जमीन के मालिक थे। वे रानी झांसी की फौज में एक सिपाही थे। जब रानी झांसी अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई तो सरदार पटेल के

पिता अंग्रेजों के बन्दी बने। जेल से छूटने के बाद वह अपने गांव में चले गये और खेती करने लग गये। सरदार पटेल भी खेती करते थे, मजदूरी करते थे। इस देश के किसान की क्या आवश्यकतायें हैं, मजदूर की क्या आवश्यकतायें हैं, इस बात का सरदार पटेल को पता था। सही अर्थों में अगर इस देश के अन्दर कोई जनवादी हो सकता था, सही अर्थों में अगर कोई समाजवादी हो सकता था, जन कल्याण वादी हो सकता था तो सरदार पटेल हो सकते थे। दुर्भाग्य है कि उनके हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं आई वह आ गई सामन्तवादियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, जो देश के सबसे अमीर आदमी थे, जिनका लालन पालन हिन्दुस्तान में नहीं, इंग्लैंड में हुआ था, जो यह समझते थे कि भारत की कोई संस्कृति नहीं है। आर्थिक दुर्दशा का यह सब से बड़ा कारण है। उन्होंने योजनायें बनाई रूस से प्रेरणा ग्रहण करके, उसके आधार पर। हैवी इंडस्ट्रीज पर बल दिया, खेती को इगनोर किया। उत्पादन को इगनोर किया। अगर हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। साथ ही साथ अगर हमने उत्पादन बढ़ाया तो वह खपा नहीं तब भी काम नहीं चल सकेगा। इस वास्ते लोगों के लिये रोजगार का प्रबन्ध करना होगा। अगर यह सब नहीं होता है तो हम क्या बांटेंगे? गरीबी बांटेंगे? समाजवाद का नारा लगाया जाता है। यह गरीबी बांटने का नारा है। हम चाहते हैं देश के अन्दर समृद्धि बांटी जाये और समृद्धि बांटने के लिये हमें अपनी आर्थिक नीतियों को इस प्रकार का मोड़ देना होगा कि उत्पादन बढ़ सके।

साथ ही दूसरा हमारे देश का बुनियादी सवाल है बेकारी का। चार करोड़ आज बेरोजगार हैं। अगर हमने उत्पादन बढ़ा भी लिया लेकिन अगर लोगों के हाथ में काम नहीं उनकी जेब में पैसा नहीं तो वह उत्पादन किस काम का होगा? इस वास्ते दूसरी आवश्यकता यह है कि हम अपने देश में एम्प्लायमेंट ओरियेंटिड इकनोमी चलायें। अधिक पैदा करें और अधिक हाथों के द्वारा पैदा करें।

हमारा देश गांवों में रहता है। अस्सी परसेंट लोग गांवों में रहते हैं। 23 साल तक हमारा सारा जोर शहरों पर रहा है। आंकड़े बताए जायें कि कितना रुपया गांवों के विकास पर खर्च किया गया है और कितना शहरों के विकास पर किया गया है। गांवों की जनता की उपेक्षा की गई है। जरूरत इस बात की है कि कि विल्लेज ओरियेंटिड इकोनोमी हम चलायें और अधिक ध्यान गांवों की ओर दें। गांवों में हमारे देश की बुनियादी इन्डस्ट्री खेती है जिस के ऊपर 73 प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं। जब तक हमारी खेती पिछड़ी रहेगी, हम खेती को उन्नत नहीं करेंगे तब तक हमारा काम न चल सकेगा। उस सब का इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। काफी उस पर प्रकाश माननीय सदस्यों ने डाल दिया है। जब तक खेती उन्नत नहीं होती है तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अपनी इकोनोमी के ढांचे में हमें आमूल चूल परिवर्तन लाने होंगे। समाजवाद के नारे से छुटटी पानी होगी। देश की इकोनोमी को एम्प्लायमेंट ओरियेंटिड, प्रोडक्शन ओरियेंटिड, विल्लेज ओरियेंटिड, एग्रिकलचर ओरियेंटिड बनाना होगा।

साथ ही साथ जितनी भी फिजूल खर्चियां हो रही हैं, इनको रोकना होगा। जो चीप फारेन एड आती है, उसको बन्द करना होगा। इस फारेन एड लाभ चन्द लोगों को होता है लेकिन उसके कारण देश में मुद्रा स्फीति होती है, कीमतें बढ़ती हैं और उसका बोझ गरीबों पर पड़ता है। अगर कोई किसी की जेब कतरता है तो उसको जेब कतरा कहा जाता है, उसको चोर कहा जाता है। लेकिन यह सरकार मुद्रा स्फीति की नीति अपना कर हर रोज दिन दिहाड़े जनता की जेब पर डाका डालती है।

[श्री बलराज मधोक]

आज अगर मेरे पास एक रुपया है और कल को कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसी एक रुपये की कीमत नब्बे पैसे रह जाती है। इस प्रकार यह सरकार इस देश की गरीब जनता की जेब पर हर रोज डाका डाल रही है। यह मुद्रा स्फीति की नीति बन्द होनी चाहिये। आसानी से जो फारेन एड मिलती है उसके कारण चन्द लोगों के हाथ में रुपया केन्द्रित किया जा रहा है। जब तक यह बन्द नहीं होती है तब तक कीमतें बढ़ती रहेंगी और कीमतें बढ़ती रहेंगी तो कामन मैन पिस्ता रहेगा। अगर कीमतों का बढ़ना रोकना है तो हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर मूल रूप से विचार करना होगा और उन में परिवर्तन करना होगा।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो प्रस्ताव हैं इस पर कब तक चर्चा होगी और दूसरा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा।

सभापति महोदय : इसके समाप्त होने के बाद ही दूसरा आयेगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस पर कितना समय बाकी है ?

सभापति महोदय : मैं देख कर बताता हूँ।

श्री गंगा रेड्डी।

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : मंहगाई के बारे में जो बहस हो रही है उस में हिस्सा लेने के लिए आपने जो मुझे वक्त दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। मंहगाई इस हद तक बढ़ गई है कि यह परेशानी का बायस बनी हुई है। हमारे रुपये की क्या हालत है, इसको आप देखें। हम मशरिक के ममालिक के दौरे पर गए थे। वहां हमने देखा कि डालर ब्लैक में बिक रहा था। आपकी करेंसी को कोई पूछता तक नहीं था।

पैसे की क्या कीमत हमारे अपने मुल्क में हैं, इनको भी आप देखें। भिखारी भीख मांगता है। वह कहता है कि पांच पैसे, दस पैसे दो। एक पैसा दो पैसा वह भी नहीं माँगता है। मुझे पता नहीं क्यों गवर्नमैंट ने एक पैसे और दो पैसे के सिक्के बनाने की तकलीफ गवारा की।

अगर हमारे जराये को सही तौर पर डेवेलप किया जाता, तो आज मुल्क की यह दशा न होती। हमारा देश एक कृषक देश है, मगर पहली और दूसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम पैसा दिया गया और जराये को डेवेलप नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सका। आज हमारे देश की पर-कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। हमारे यहां एक आदमी की फी-साल औसत आमदनी 750 रुपये है, जबकि जापान जैसे मुल्क में एक आदमी की फी-साल औसत आमदनी 8250 रुपये है, जहां गुजिश्ता पंद्रह बरसों में इकोनामी 600 फीसदी बढ़ी और 1970 में 14 फीसदी बढ़ी। जब जापान जैसा मुल्क, जहां कोई खास जराये नहीं हैं, दूसरी जंग में तबाह होने के बाद भी इतनी तरक्की कर सकता है, तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

जराअत के बारे में जो लापरवाही बरती गई है, वह तो सब पर वाजेह है अगर गवर्नमेंट कहती है कि आज जराअत में जो तरक्की हुई है, वह उसकी वजह से हुई है, तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ज्यादा कीमतों की वजह से काश्तकारों को बढ़ावा मिला और इस लिए उन्होंने ज्यादा उत्पादन किया, जिस की वजह से जराअत बढ़ी। आज सरकार कहती है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है, लेकिन वह काश्तकारों की हालत को नहीं समझती है। वह यह नहीं देखती है कि पैदावार करने के लिए खाद, मजदूरी और जिन दूसरी

चीजों की जरूरत होती है, उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। कीमतों के बारे में सरकार की पालिसी यह है कि इस साल कीमतें मुकर्रर करके एफ० सी० आई० द्वारा धान और मक्की वगैरह खरीदने के एहकाम जारी किये गये थे। मैं एक ऐसी कांस्टीट्यूएन्सी से आता हूं, जहां एक बहुत बड़ा मार्केट निजामाबाद है, जहां पांच लाख क्विंटल मक्की आई थी। एफ० सी० आई० ने उसमें से पांच फीसदी से कम खरीद की। लेकिन जब उसने खरीदना बन्द कर दिया, तो कीमतों में दस रुपये की कमी हो गई। इससे बीच के व्यापारियों ने लाखों रुपये का फायदा उठाया और जिन काश्तकारों ने चार माह तक मेहनत करके और पैसा लगाकर उत्पादन किया, उनका नुकसान हुआ। अगर गवर्नमेंट की यही नीति रही और काश्तकारों के साथ उसका यही बर्ताव रहा, तो उसको मायूसी होगी और उत्पादन मे इजाफा नहीं बल्कि कमी होगी।

आज मजदूरों का क्या हाल है। रोज अखबारों में लिखा होता है कि कहीं न कहीं हड़ताल हो रही है, कारखाने बन्द हो रहे हैं, तोड़-फोड़ होती है, लाक-आउट होता है। आपने सुना होगा कि पंजाब के गवर्नमेंट एम्पलाईज की कम्पलीट हड़ताल हुई है। एयर-लाइन्ज में अभी भी स्ट्राइक चल रही है। क्या गवर्नमेंट यह उम्मीद कर सकती है कि उसकी इस लेबर पालिसी से मुल्क का भला होगा? वह क्यों नहीं कम्पलसरी आरबिट्रेशन एक्ट पास करके स्ट्राइक्स को बैन कर देती? उससे शायद मेरे जैसे लोगों को लीडर बनने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन देशभक्ति और मुल्क के फायदे को सामने रखते हुए सरकार को स्ट्राइक्स को बैन कर देना चाहिए और आरबिट्रेशन के लिए एक कौंसिल बनानी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट, एम्पलायर्ज और एम्पलाईज के नुमायंदे हों और उस कौंसिल का फैसला लाजिमी करार दिया जाये। जब तक चौबीस घण्टे काम नहीं होगा, तब तक देश का भला नहीं होगा। जापान में यह हालत है कि मजदूर स्ट्राइक का नोटिस सर्व करते हैं और पट्टी बांध कर काम करते हैं। हमारे मुल्क में मजदूर कल तक जिस मिल में काम करते हैं, आज वे उसको आग लगाते हैं। मिलें चाहे किसी की भी मिल्कियत हों। लेकिन क्या मालिक ही उनसे जीते हैं, क्या मजदूरों को मिलों से रोजगार नहीं मिलता है? यह नजरिया बदलना चाहिए। शायद कुछ दोस्त इस बात से सहमत न हों, लेकिन मुझे अपने व्यूज यहां पर रखने का अख्त्यार है।

सरकार ने कई लाख रोजगार पैदा किये, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ती गई। जैसा कि किसी ने कहा है, "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की।" चूंकि आबादी में इजाफा हो हो रहा है, इस लिए बगैर जराये को डेवेलप किए हुए रोजगार फराहम करने से वही होगा, जो आन्ध्र प्रदेश में हुआ है।

श्री बलराज मधोक : हमारे देश में आबादी बहुत नहीं बढ़ी है। दूसरे देशों के मुकाबले में, जापान और जर्मनी के मुकाबले में, हम अंडर-पापुलेटिड हैं, हम ओवर-पापुलेटिड नहीं हैं। यह केवल एक धोखा है। यह सरकार केवल बहाना बनाती है कि चूंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं।

श्री गंगा रेड्डी : अगर हम जराये डेवेलप न करें और रोजगार पैदा करते जायें, तो वही हालत होगी, जो आन्ध्र प्रदेश में हुई, जहां तेलंगाना एजीटेशन के जमाने में सुपर-न्युमरेरी पोस्ट्ज क्रीएट की गई। लिहाजा पहले जराये को डेवेलप किया जाये और फिर रोजगार पैदा किये जायें। मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि उसकी रिक्रूटिंग की पालिसी बिल्कुल गलत है। आज भी हमारे मुल्क में आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० आर० एस० को बहुत अहमियत दी जाती है। हमें एडमिनिस्ट्रेटर्ज की कतई जरूरत

[श्री गंगा रेड्डी]

नहीं है। अगर कालेज के तीन लड़कों में से एक एसिस्टेंट इंजीनियर बनता है, दूसरा मेडिकल आफीसर बनता है और तीसरा किसी टेक्निकल पोस्ट में न जाकर आई० ए० एस० वगैरह में चला जाता है, तो वह तो सैक्रेटरी बन जाता है, जबकि पहले दो को कोई तरक्की नहीं मिलती है। जब तक इस जाब-ओरियंटिड पालिसी को बदला नहीं जायेगा, तब तक मुल्क की दुर्गति दूर नहीं होगी।

हमारे गावों में मुल्क की अस्सी फीसदी आबादी रहती है। इसलिए उनको डेवेलप किया जाय। शहरों पर ज्यादा तवज्जुह न दे कर गावों की उन्नति की जानी चाहिए।

पब्लिक सेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह बहुत कान्ट्रोवर्शल इस्यू है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस पब्लिक सैक्टर में मुसलसल नुक्सान हो रहा है, अगर उसको बन्द नहीं किया जायेगा, तो यह कोई सेहतमन्द इलामत नहीं है। इस नुक्सान से मुल्क का सरमाया तबाह हो रहा है। यह सरकार इस मुल्क के मुसीबतजदा टैक्सपेयर्ज का पैसा खर्च करने के काबिल नहीं है, जिनमें गरीब लोग भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर आन्ध्र में आर० टी० सी० की लगभग तीन हजार बसें चलती हैं, लेकिन उसमें नहीं के बराबर मुनाफा होता है। अगर उसको पब्लिक सैक्टर से निकाल दिया जाये, तो पच्चीस करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। सरकार किसी आइडियालोजी के लिए मुल्क के सरमाया को तबाह नहीं कर सकती है और उसकी इकोनामी को धक्का नहीं पहुँचा सकती है। अगर प्राडक्शन बढ़ेगा तभी बेरोजगारी दूर होगी। वर्ना हम क्या बांटेंगे ? अगर हम प्रासपेरिटी नहीं बांटेंगे, तो क्या पावर्टी, इफलास और गुरबत को बांटेंगे ?

ला एंड आर्डर और डिसिप्लिन सबके लिए जरूरी है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बंगाल और मुल्क के गोशे-गोशे में ला एंड आर्डर की हालत खराब है। जब तक जानो-माल और इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, तब तक हम किसी भी मैदान और शोबे में तरक्की नहीं कर सकते हैं। हमारी सरहदों पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से खतरा है। अगर हम आर्थिक लिहाज से मजबूत नहीं होंगे, तो हम देश की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा :

> "गर न समझोगे, तो मिट जाओगे
> हिन्दुस्तां वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी
> न होगी दास्तानों में।"

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, मेरे मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आप को मालूम है और माननीय सदस्या, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, ने अपने भाषण में कहा है कि आज सारे हिन्दुस्तान में लगभग बाईस लाख सरकारी कर्मचारी इस बढ़ती हुई मंहगाई के खिलाफ डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनको पन्द्रह रुपये से लेकर 45 रुपये तक की जो अन्तरिम सहायता दी गई है, उसकी मुखालिफत करने के लिए वे लोग यहां इकट्ठे हुए है। वे हजारों की तादाद में इस लोक सभा के दरवाजे को भी खटखटाना चाहते थे और अपनी फरियाद सुनाना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती इस देश की है कि हमारे पार्लियामेंट में होने के बावजूद आजादी के बाद से और खासकर पांच छः सालों से, यहां दफा 144 लगी हुई है। जिस जनता कि वजह से हम यहां पर बैठे हुए हैं, मालूम होता है कि वह जनता यहां आकर अपनी कोई फरियाद नही कर सकती है।

सभापति महोदय : श्री बनर्जी अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, यह गारन्टी दे दीजिये कि आगे सेशन होगा।

सभापति महोदय : यह मेरे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है । इससे पहले कि मैं श्री रामावतार शास्त्री को आध घंटे की चर्चा प्रारम्भ करने के लिए कहूं, श्रम मंत्री, श्री भागवत झा आजाद, कुछ घोषणा करेंगे ।

17.28 hrs.

STATEMENT RE : APPOINTMENT OF AN EMPLOYMENT COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Sir, it may kindly be remembered that this House passed a resolution for the appointment of an Employment Commission. The Employment Commission would consist of the following :

CHAIRMAN : Mr. B. Bhagwati, MLA, Assam, who was a member of this House.

M.P's. : 1. Shri Jyotirmoy Basu, Member of Lok Sabha.

2. Shri M. Anandam, Member of Rajya Sabha.

ECONOMIST : Dr. Gautam Mathur of Osmania University.

EMPLOYMENT COMMISSIONER : Shri V. L. Gidwani.

NOMINEES OF CENTRAL MINISTRIES :

(i) Dr. Ashok Mitra, Chief Economic Adviser Department of Economic Affairs.

(ii) Shri K. Balachandran, Additional Secretary, Industrial Development.

(iii) Shri J. C. Mathur, Additional Secretary, Department of Agriculture.

NOMINEES OF THE STATE GOVERNMENTS :

(i) Government of West Bengal —Shri D. N. Banerjee, Special Officer and Ex-Officio Secretary, Home Department.

(ii) Government of Madhya Pradesh : Shri N. Sundaram, Development Commissioner.

MEMBER-SECRETARY : Shri N.S. Pandey.

The proposed terms of reference of the Committee of Experts on Unemployment are :

(i) To assess the extent of unemployment and underemployment in all its aspects, taking into account the recommendations made by the Committee of Experts on Unemployment Estimates set up by the Planning Commission under the Chairmanship of Prof. M. L. Dantwala.

(ii) To recommend the directions in which the programmes included in the Fourth Five-Year Plan could be n ade more employment-oriented in their implementation, with due regard to their timely execution, economy and productivity and to the requirements of rapid economic development.

(iii) To suggest suitable strategies for employment generation, both short-term, and long-term, including technical, financial and fiscal measures, in respect of different sectors of the economy, taking into account the mobility of labour and the openings for employment and self-employment in the tertiary sector as a result of implementation of the Plan programmes and various measures initiated by the Government for activating the economy.

(iv) To suggest specific programmes for promoting productive employment and self-employment of the educated unemployed in general and the unemployed technical personnel such as engineers, technicians, etc. in particular, and to suggest measures to rectify the imbalance between the out turn of educated and technical persons on the one hand and the available employment opportunities on the other.

(v) To suggest a suitable machinery at the Centre and State level for continuous appraisal of the changing employment and manpower